

GUPTA

CLASSES

Current Affairs

September 2024

Hindi

Part-1



GUPTA

CLASSES

Current Affairs Q&A PDF – September 2024

Table of Contents

NATIONAL AFFAIRS	5
INTERNATIONAL AFFAIRS	29
GOVT SCHEMES	33
VISITS	40
BANKING AND FINANCE	44
ECONOMY AND BUSINESS	70
MoU's AND AGREEMENTS	77
APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS	87
AWARDS AND RECOGNITIONS	102
SUMMITS, CONFERENCES	109
COMMITTEE AND MEETING	115
INDEX	117
ACQUISITION AND MERGERS	128
DEFENCE	133
SCIENCE AND TECHNOLOGY	141
SPORTS	146
BOOKS AND AUTHORS	156
OBITUARY	157
IMPORTANT DAYS	160
ENVIRONMENT	181
APP and WEB PORTAL	183
CURRENT STATIC BANKING	188
CA STATIC GK	210

NATIONAL AFFAIRS

1. निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) को हाल ही में (अगस्त'24 में) "नवरत्न का दर्जा" नहीं दिया गया है?

- 1) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
 - 2) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 - 3) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन
 - 4) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
 - 5) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- उत्तर- 5) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को "नवरत्न का दर्जा" प्रदान किया है। इनमें RailTel कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (RCIL), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) शामिल हैं।

- इसके साथ ही, नवरत्न CPSE की संख्या 21 से बढ़कर 25 हो गई है।
- नवरत्न योजना 1997 में शुरू की गई थी। नवरत्न का दर्जा पाने के लिए पात्र CPSE को मिनीरत्न I, अनुसूची 'A' होना चाहिए, पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) की रेटिंग 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' होनी चाहिए, और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए।
- नई दिल्ली, दिल्ली स्थित RCIL, जो रेल मंत्रालय के तहत एक 'मिनी रत्न' PSU है, को 22वें नवरत्न CPSE के रूप में अपग्रेड किया गया है।
- नई दिल्ली स्थित SECI लिमिटेड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-I CPSE को 23वें नवरत्न CPSE के रूप में अपग्रेड किया गया है।
- फरीदाबाद, हरियाणा स्थित NHPC, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी-I CPSE को 24वें नवरत्न CPSE के रूप में अपग्रेड किया गया है।
- शिमला, हिमाचल प्रदेश (HP) स्थित SJVN, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न, श्रेणी-I और अनुसूची 'A' CPSE, को 25वें नवरत्न CPSE के रूप में अपग्रेड किया गया है।

2. युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYAS) ने राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त, 2024) के अवसर पर RESET कार्यक्रम शुरू किया।

RESET के संक्षिप्त नाम में 'E' अक्षर क्या दर्शाता है?

- 1) एनरिचमेंट
- 2) एम्पावरमेंट
- 3) एंटेप्रेन्योरशिप
- 4) एजुकेशन
- 5) एंगेजमेंट

उत्तर- 2) एम्पावरमेंट

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYAS), ने राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त, 2024) के अवसर पर नई दिल्ली, दिल्ली में 'रिटायर्ड स्पोर्ट्सपर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग' (RESET) कार्यक्रम शुरू किया।

- इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों को करियर विकास और रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करके उनका समर्थन करना है।

- ग्वालियर, मध्य प्रदेश (MP) स्थित **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE)** RESET कार्यक्रम के पायलट चरण का नेतृत्व करेगा, जो सेल्फ-पेस्ड मॉड्यूल, ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग और इंटरनशिप के साथ हाइब्रिड लर्निंग प्रदान करता है।
- RESET कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को अपने अद्वितीय कौशल को महत्वाकांक्षी एथलीटों के साथ साझा करने में सक्षम बनाकर पीढ़ीगत अंतराल को पाटता है।
- इसका उद्देश्य **20-50 वर्ष** की आयु के एथलीटों को सशक्त बनाना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

3. 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) 14,235.30 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए सात प्रमुख योजनाएँ है।

B) सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CSS) ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 26,000 करोड़ रुपये के 240 एयरो-इंजन की खरीद को मंजूरी दी है।

C) अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत चौथी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल B

5)सभी A, B & C

उत्तर- **1)केवल A & B**

स्पष्टीकरण:

2 सितंबर 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है:

i. 14,235.30 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए सात प्रमुख योजनाएँ है।

ii. गुजरात के साणंद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत 5वीं सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना है।

iii. सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CSS) ने HAL से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 26,000 करोड़ रुपये के 240 एयरो-इंजन खरीदने को मंजूरी दी है।

iv. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों यानी मुंबई (महाराष्ट्र) और इंदौर (मध्य प्रदेश, MP) के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर (km) लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

4. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा अनुमोदित पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) DAC केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1,44,716 करोड़ रुपये के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की।

B) परिषद ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने तथा फायरिंग समाधान प्रदान करने के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

C) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) द्वारा डिजाइन और विकसित मशीनीकृत संचालन के दौरान इन-सीट मरम्मत के लिए फॉरवर्ड रिपेयर टीम (ट्रैकड) वाहनों के लिए भी मंजूरी दी गई।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल B

5)सभी A, B & C

उत्तर- 5)सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

3 सितंबर, 2024 को, केंद्रीय मंत्री **राजनाथ सिंह**, रक्षा मंत्रालय (MoD) की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए 1,44,716 करोड़ रुपये के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की।

- खरीदें (भारतीय) और खरीदें (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणियों के तहत लागत का 99% स्वदेशी स्रोतों से है।
- परिषद ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने तथा फायरिंग समाधान प्रदान करने के लिए **वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार** के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
- मशीनीकृत संचालन के दौरान इन-सीट मरम्मत के लिए **फॉरवर्ड रिपेयर टीम** (ट्रैकड) वाहनों के लिए भी मंजूरी दी गई, जिसे चेन्नई, तमिलनाडु (TN) स्थित **आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL)** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उपयोग मशीनीकृत इन्फैंट्री बटालियन और आर्मर्ड रेजिमेंट दोनों द्वारा किया जाएगा।
- बढ़ी हुई समुद्री निगरानी के लिए **डोर्नियर-228 विमान** की खरीद।

5. नव अधिसूचित 'दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) इन नए नियमों का उद्देश्य 'डिजिटल भारत निधि (DBN)' पहल के प्रबंधन और कार्यान्वयन को बढ़ाना है।

B) DBN, 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत बनाए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (USOF) की जगह लेगा।

C) भारत सरकार USOF के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों से दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 3% शुल्क लेती है।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल B

5)सभी A, B & C

उत्तर- 1)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय (MoC) ने दूरसंचार पहुँच को बढ़ावा देने के लिए 'दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024' को अधिसूचित किया है। इन नए नियमों का उद्देश्य दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24(1)के तहत स्थापित 'डिजिटल भारत निधि (DBN)' पहल के प्रबंधन और कार्यान्वयन को बढ़ाना है।

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (USOF)**, जिसे मूल रूप से 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, का नाम बदलकर DBN कर दिया गया है।
- सरकार दूरसंचार ऑपरेटरों से USOF के लिए धन एकत्र करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 5% लेवी वसूलती है।
- नए नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 523 से 527 की जगह लेते हैं, जो यह निर्धारित करते थे कि USOF कैसे काम करेगा। हालाँकि, नए नियम अपनी समाप्ति तिथि तक मौजूदा व्यवस्था को रद्द नहीं करेंगे।
- DBN से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिनका उद्देश्य वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में **दूरसंचार सेवाओं में सुधार** करना है, और वंचित समूहों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है।

6. महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा किस महीने को 'राष्ट्रीय पोषण माह 2024 या नुट्रिशन मंथ 24' के रूप में मनाया गया?

- 1) जुलाई
- 2) सितंबर
- 3) अक्टूबर
- 4) अगस्त
- 5) नवंबर

उत्तर- 2) सितंबर

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) की मंत्री **अन्नपूर्णा देवी यादव** ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'राष्ट्रीय पोषण माह 2024 या नुट्रिशन मंथ 24' का शुभारंभ किया।

- यह राष्ट्रीय पोषण अभियान की **7वीं** श्रृंखला है, जो **पूरे सितंबर महीने** को **पोषण माह** के रूप में मनाती है।
- महीने भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के प्रयासों को और तेज करना और पूरे भारत में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
- 2018 में, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियों और छह साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य पर जोर देकर कुपोषण को दूर करने के लिए '**राष्ट्रीय पोषण अभियान**' शुरू किया।
- राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी (PBPB), बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

7. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए _____ भारत के विधि आयोग (LCI) को मंजूरी दी है।

- 1) 20वां
- 2) 21वां
- 3) 22वां
- 4) 23वां
- 5) 24वां

उत्तर- 4) 23वां

स्पष्टीकरण:

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए **23वें भारत के विधि आयोग (LCI)** को मंजूरी दी है। आयोग कानूनी सुधारों और कानूनी प्रणाली में सुधार की समीक्षा और सिफारिश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- **23वें विधि आयोग** में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित), एक सचिव, विधि मामलों का विभाग एक पदेन सदस्य, विधायी विभाग का सचिव एक पदेन सदस्य तथा अधिकतम पाँच अंशकालिक सदस्य होंगे।
- स्वतंत्र भारत का **पहला विधि आयोग 1955** में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल, **M. C. सीतलवाड़** इस आयोग के अध्यक्ष थे।
- **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी** की अध्यक्षता वाली **22वीं LIC** एक साथ चुनाव और समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट पर काम कर रही थी, लेकिन मार्च 2024 में अवस्थी के लोकपाल के सदस्य बनने से पहले उन्होंने सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी थी।

8. भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार पर लागू संसद द्वारा अधिनियमित किसी कानून के तहत किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन करने और उन्हें नियुक्त करने की शक्तियां किसे सौंपी हैं।

- 1) उपराज्यपाल
- 2) प्रधानमंत्री
- 3) मुख्यमंत्री
- 4) लोकपाल अध्यक्ष
- 5) भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर- 1) उपराज्यपाल

स्पष्टीकरण:

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने और उसके सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियाँ सौंपी हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार पर लागू होती हैं।

- संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- दिल्ली NCT सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 45D प्राधिकरणों, बोर्डों, आयोगों या वैधानिक निकायों की नियुक्ति करने की शक्ति से संबंधित है।

9. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का नाम बताइए जिसे हाल ही में (सितंबर'24 में) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।

- 1) eSankhyiki
- 2) बीमा सेंट्रल
- 3) विश्वस्य
- 4) भूसखलन
- 5) eSwasthya Dham

उत्तर- 3) विश्वस्य

स्पष्टीकरण:

4 सितंबर 2024 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव S. कृष्णन ने 'विश्वस्य'- ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया। इसे विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस ढांचे का उद्देश्य अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देना और डिजिटल सेवा वितरण में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है।
- MeitY ने विश्वस्य BaaS के अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला जैसे ई-स्टाम्प समाधान, न्यायपालिका आवेदन, सहमति प्रबंधन ढांचा, अधिवास प्रमाण पत्र श्रृंखला, कृषि उपज की ट्रैकिंग, अन्य का भी अनावरण किया।
- MeitY ने 'NBFLite'-लाइटवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, 'प्रामाणिक' और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल भी लॉन्च किया।
- NBFLite एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों जैसे: अनुप्रयोगों का तेजी से प्रोटोटाइप बनाने, अनुसंधान करने और क्षमता निर्माण करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है।
- प्रामाणिक मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) की उत्पत्ति और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को सत्यापित करने के लिए एक अभिनव ब्लॉकचेन-सक्षम समाधान है, जो देश भर में ब्लॉकचेन पहलों का समर्थन करता है।
- पोर्टल NBF पहल से संबंधित सामग्री का प्रबंधन करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (CMS) पर आधारित है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

विकल्प संशोधन:

1. जुलाई 2024 में कवर किया गया: eSankhyiki

सांख्यिकी मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) ने eSankhyiki पोर्टल (<https://esankhyiki.mospi.gov.in/>) लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो योजनाकारों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा।

2. मई 2024 में कवर किया गया: बीमा सेंट्रल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नवाचार के साथ ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए भारत का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म बीमा सेंट्रल पेश किया। इसने बीमा सेंट्रल के साथ सहयोग किया है जिसे CAMS इंश्योरेंस रिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CAMSRRep) द्वारा विकसित किया गया था।

4. जून 2024 में कवर किया गया: भूखलन

i. केंद्रीय मंत्री गंगापुरम (G) किशन रेड्डी, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल (WB) में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), धारित्री परिसर, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में राष्ट्रीय भूखलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC) का उद्घाटन किया।

ii. उन्होंने भूसंकेत वेब पोर्टल और भूखलन मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) भी लॉन्च किया।

Dear Aspirants,

We have introduced a new explanation section called “Option Revision”

Exclusively on our Daily CA App Quiz. It will help aspirants to revise last 4 months CA via options. The news theme, relevant topic, and importance are taken into consideration when choosing an option.

Question No. 9 gives you preview about option revision., Aspirants can get option revision for rest of questions on our Daily CA App Quiz (Explanation part)

We would like to notify you that all kind of Question & Answer (Q&A) PDF for paid subscribers will be discontinued from December 31 2024.

Subscribers can attend the Quiz as Usual!!!

10. भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम बताइए जिसे हाल ही में (सितंबर'24 में) केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था?

1) PRAGATI-2024

2) Ideas4LiFE

3) SABB

4) VisioNxt

5) e-FAST इंडिया

उत्तर- 4) VisioNxt

स्पष्टीकरण:

5 सितंबर 2024 को, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 'VisioNxt' – ट्रेड इनसाइट और फोरकास्टिंग लैब लॉन्च की, जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIFT) द्वारा विकसित भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इमोशनल इंटेलिजेंस (EI) सक्षम ट्रेड पूर्वानुमान पहल है।

- उन्होंने 'VisioNxt' का द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) वेब पोर्टल और भारत की पहली फैशन ट्रेंड बुक 'परिधि 24x25' भी लॉन्च की।
- VisioNxt की स्थापना 2017 ग्लोबल टेक्सटाइल समिट के जवाब में की गई थी, जहाँ भारत-विशिष्ट फैशन ट्रेंड इनसाइट्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।
- इसका उद्देश्य भारत के फैशन उद्योग के लिए स्थानीयकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करके वैश्विक पूर्वानुमान एजेंसियों पर निर्भरता को कम करना है।
- मुख्य विशेषताओं में एक अद्वितीय AI मॉडल, "डीपविज़न" शामिल है, जो भारतीय और पश्चिमी परिधानों की 100 से अधिक श्रेणियों का विश्लेषण करने में सक्षम है।

11. हाल ही में (सितंबर'24 में) किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में 10 सबसे बड़े राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है?

1) अरुणाचल प्रदेश

2) असम

3) कर्नाटक

4) तेलंगाना

5) हरियाणा

उत्तर- 4) तेलंगाना

स्पष्टीकरण:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना, तमिलनाडु (TN) और राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में 10 सबसे बड़े राज्यों में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है।

- भारत के 9वें सबसे बड़े राज्य तेलंगाना ने FY24 में 9.2% की दर से अपनी GSDP वृद्धि देखी और वास्तविक GSDP 7.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह वृद्धि दर FY24 में दर्ज भारत की 8.2% की GDP वृद्धि को पार कर गई है।
- तमिलनाडु (TN) जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ने 8.2% की दर से अपनी GSDP वृद्धि देखी और आकार में 15.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।
- 7वें सबसे बड़े राज्य राजस्थान ने अपने GSDP में 8% की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि दर्ज की।
- तेलंगाना, TN और राजस्थान ने सबसे अधिक GSDP वृद्धि दर्ज की, इसके बावजूद महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसका वास्तविक GSDP FY24 में 24.1 लाख करोड़ रुपये था।

12. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) दो दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव (ISF) 2024 आयोजित किया है, जिसे प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था?

1) टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड

2) इंटरनेशनल सोलर अलायन्स

3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी

4) JSW नियो एनर्जी लिमिटेड

5) इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी

उत्तर- 2) इंटरनेशनल सोलर अलायन्स

स्पष्टीकरण:

5 सितंबर 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायन्स (ISA) द्वारा भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव (ISF) 2024 को वर्चुअली संबोधित किया।

- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है। इसने 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा विकसित करना है।

13. मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट- ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) के लिए नए उपचार का नाम बताइए जिसे हाल ही में (सितंबर'24 में) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- 1) PREFIRE
- 2) NIRMAN
- 3) प्रवाह
- 4) BPaLM
- 5) सक्षम

उत्तर- 4) BPaLM

स्पष्टीकरण:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने भारत में राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) के लिए एक नए उपचार 'BPaLM' की शुरूआत को मंजूरी दे दी है।

i. BPaLM रेजिमेन में चार दवाएँ, जैसे बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन शामिल हैं, जो पिछली मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) उपचार प्रक्रिया की तुलना में अधिक सुरक्षित, प्रभावी और तेज़ उपचार विकल्प हैं।

ii. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP), जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) के रूप में जाना जाता था, का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से पांच साल पहले 2025 तक भारत में TB को खत्म करना है।

14. किस राज्य के परिवहन निगम ने हाल ही में (सितंबर'24 में) पूरे भारत में कैशलेस यात्रा के लिए भारत का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च किया है?

- 1) कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC)
- 2) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC)
- 3) हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC)
- 4) तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC)
- 5) गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC)

उत्तर- 3) हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC)

स्पष्टीकरण:

हिमाचल प्रदेश (HP) के मुख्यमंत्री (CM) सुखविंदर सुखू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में, भारत भर में कैशलेस यात्रा के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) को लॉन्च किया, जिससे उपयोगकर्ता बिना नकदी के देश भर में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकेंगे।

- भारत में पहला यह कार्ड, पूरे भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में कैशलेस यात्रा की अनुमति देता है, जिससे HRTC इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला राज्य परिवहन उपक्रम (STU) बन गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सहयोग से विकसित HRTC NCMC कार्ड, एक संपर्क रहित, दोहरे इंटरफ़ेस वाला, यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा (EMV)-चिप-आधारित प्रीपेड कार्ड है।

15. इस्पात मंत्रालय (MoS) ने हाल ही में (सितंबर'24 में) किस शहर में "ग्रीनिंग स्टील: पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी" नामक कार्यक्रम की मेजबानी की है?

- 1) भिलाई, छत्तीसगढ़
- 2) जमशेदपुर, झारखंड
- 3) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
- 4) नई दिल्ली, दिल्ली
- 5) बोकारो, झारखंड

उत्तर- 4) नई दिल्ली, दिल्ली

स्पष्टीकरण:

10 सितंबर 2024 को, इस्पात मंत्रालय (MoS) ने C.D देशमुख हॉल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित "ग्रीनिंग स्टील: पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी" नामक कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी की।

- कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात मंत्री H. D. कुमारस्वामी ने "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान" पर रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट में रखी गई प्रमुख रणनीतियाँ और कार्य योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (NDC) में निर्दिष्ट शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप भी हैं।
- भारत में स्टील सेक्टर भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का **12%** हिस्सा है, जिसमें प्रति टन कच्चे इस्पात में 2.5 टन CO₂ उत्सर्जन होता है, जबकि वैश्विक औसत प्रति टन कच्चे इस्पात में 1.9 टन CO₂ उत्सर्जन होता है।
- **संजय सिंह, पूर्व सचिव, MoS** ने कार्यक्रम के दौरान "लीडरशिप एंड इनोवेशन: ड्राइविंग द ग्रीन स्टील ट्रांजिशन" नामक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। सत्र में टिकाऊ इस्पात उत्पादन को आगे बढ़ाने में दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

16. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) 10 सितंबर, 2024 से विलय नियंत्रण व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया है?

- 1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
 - 2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
 - 3) संचार मंत्रालय
 - 4) महिला और बाल विकास मंत्रालय
 - 5) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- उत्तर- 5) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

10 सितंबर, 2024 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 10 सितंबर, 2024 से विलय नियंत्रण व्यवस्था को नया रूप देने के लिए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया।

- इन परिवर्तनों का उद्देश्य विलय समीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लेन-देन की अधिसूचना का आकलन करने के लिए नए मानक पेश करना है।
- ये नियम **2,000 करोड़ रुपये** से अधिक के सौदों के लिए CCI से विनियामक मंजूरी अनिवार्य करते हैं, यदि लक्ष्य इकाई के पास "भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन (SBO)" हैं।
- **450 करोड़ रुपये** से कम की संपत्ति या 1,250 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली संस्थाओं से जुड़े लेनदेन को CCI की मंजूरी से छूट दी गई है।

17. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-संस्थागत पहल "पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च (PAIR)" शुरू की है?

- 1) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
 - 2) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
 - 3) यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन
 - 4) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन
 - 5) NITI आयोग
- उत्तर- 2) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

स्पष्टीकरण:

10 सितंबर 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) **नरेंद्र मोदी** ने नई दिल्ली, दिल्ली में अपने आवास पर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के **गवर्निंग बोर्ड** की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

- बैठक में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य और अनुसंधान और विकास (R&D) कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने पर चर्चा की गई।

- ANRF ने शीर्ष-स्तरीय संस्थानों और सीमित अनुसंधान क्षमताओं वाले संस्थानों के बीच सहयोग को सक्षम करने के लिए एक बहु-संस्थागत पहल "पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च (PAIR)" की शुरुआत की।
- ANRF ने मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (MAHA) का अनावरण किया, जो प्रमुख रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को गति देने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम है।
- ANRF सेंटर ऑफ एक्ससेलेन्स (ACE) को महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक प्रयासों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण सहायता के साथ विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए पेश किया गया था
- ANRF का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। समाधान केंद्रित अनुसंधान पर ANRF के कार्यक्रम सौर सेल, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, स्मार्ट बुनियादी ढाँचा और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- फाउंडेशन की पहल भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है, और इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत किया गया है।

18. 11 सितंबर, 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) मिशन मौसम, अनुसंधान, पूर्वानुमान और जलवायु लचीलापन बढ़ाकर भारत के मौसम और जलवायु विज्ञान में क्रांति लाने के लिए दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पहल को मंजूरी दी गई है।

B) ई-बस अपनाने को बढ़ावा देने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए 3,435.33 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ PM-eBus सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना को मंजूरी दी गई है।

C) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) 2025-26 से 2029-30 के कार्यान्वयन के लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 1)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

11 सितंबर, 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में **2,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय वाली पहल **मिशन मौसम** को मंजूरी दे दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के नेतृत्व में, इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान, पूर्वानुमान और जलवायु लचीलापन बढ़ाकर भारत के मौसम और जलवायु विज्ञान में क्रांति लाना है।
- मिशन अत्यधिक सटीक मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **FY 2024-25 (FY25) से FY 2028-29 (FY29)** तक सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (PTA) द्वारा 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की खरीद और संचालन के लिए **3,435.33 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **"PM-eBus सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना"** को मंजूरी दी।
- इस योजना का उद्देश्य ई-बस अपनाने को बढ़ावा देना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 से 2028-29 के लिए **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV)** के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तहत ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय **70,125 करोड़ रुपये** है।

- इस योजना का उद्देश्य मैदानी इलाकों, पहाड़ी राज्यों और विशेष श्रेणी के क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए **62,500** किलोमीटर (km) की सभी मौसम वाली सड़कें उपलब्ध कराना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में **10,900 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (**PM E-DRIVE**) योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (**MHI**) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- विद्युत मंत्रालय (MoP) ने **12,461 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स** (HEP) के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए बजटीय सहायता की योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना को **FY25 से FY32** तक लागू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य दूरदराज के क्षेत्रों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष **5 लाख रुपये** का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। [अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

19. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने हाल ही में (सितंबर'24 में) नई दिल्ली, दिल्ली में विज्ञान भवन में अपने पहले स्थापना दिवस समारोह में अपनी 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया था।

I4C किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- 1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 2) गृह मंत्रालय
- 3) सहकारिता मंत्रालय
- 4) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 5) रक्षा मंत्रालय

उत्तर- **2) गृह मंत्रालय**

स्पष्टीकरण:

10 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री **अमित शाह**, गृह मंत्रालय (**MHA**) और सहकारिता मंत्रालय (MoC) ने नई दिल्ली, दिल्ली में विज्ञान भवन में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (**I4C**) के **पहले स्थापना दिवस** को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने I4C के नए लोगो, विजन और मिशन का भी अनावरण किया।

- कार्यक्रम के दौरान, अमित शाह ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए **4 प्रमुख पहलों** - साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (**CFMC**), **समन्वय प्लेटफॉर्म**, **साइबर कमांडो प्रोग्राम** और **संदिग्ध रजिस्ट्री** - का शुभारंभ किया।
- **CFMC** की स्थापना नई दिल्ली, दिल्ली में I4C मुख्यालय में विभिन्न प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, पेमेंट एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) कानून प्रवर्तन एजेंसियों (**LEA**) के प्रतिनिधियों के साथ की गई है।
- **समन्वय प्लेटफॉर्म**, एक संयुक्त साइबर क्राइम जांच सुविधा प्रणाली, एक वेब-आधारित मॉड्यूल है जो साइबर क्राइम के डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण और विभिन्न राज्यों/UT के LEA के बीच समन्वय के लिए एक एकीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।
- **साइबर कमांडो प्रोग्राम** प्रशिक्षित 'साइबर कमांडो' की एक विशेष शाखा स्थापित करेगा, जिन्हें साइबर सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस पहल के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर **साइबर संदिग्ध रजिस्ट्री** बनाई जाएगी और राज्य स्तर की रजिस्ट्रियों को जोड़कर साइबर क्राइम से लड़ने के लिए साझा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

20. सितंबर 2024 में नई दिल्ली, दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्रालय (MPA) की 100-दिवसीय उपलब्धियों के हिस्से के रूप में छह पहलों में से कौन-सी पहल 'नहीं' शुरू की गई है?

- 1) नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन
 - 2) NeVA पब्लिक पोर्टल वर्शन 2.0
 - 3) कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम
 - 4) एग्रीकल्चरल सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेल्स
 - 5) NYPS फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलज
- उत्तर- 4) एग्रीकल्चरल सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेल्स

स्पष्टीकरण:

11 सितंबर, 2024 को, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्रालय (MPA) ने नई दिल्ली, दिल्ली में MPA की 100-दिवसीय उपलब्धियों के हिस्से के रूप में छह पहलों की शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य निर्णय लेने में सुधार करना, वास्तविक समय के शासन को आगे बढ़ाना और कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना है।

- नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA 2.0) के उन्नत संस्करण में अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और राज्य विधायी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर एकीकरण की सुविधा होगी।
- NeVA पब्लिक पोर्टल वर्शन 2.0 का उन्नत संस्करण कागज़ रहित विधायी वातावरण प्राप्त करने और वास्तविक समय के शासन को बढ़ावा देने के लिए सॉफ़्टवेयर को बेहतर बनाएगा।
- अधीनस्थ विधान समिति (COSL) की 28वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर, एक पोर्टल सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम (SLMS) विकसित किया गया, जो विभिन्न हितधारकों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए एकल विंडो इंटरफ़ेस प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ विधान समिति के लिए बेहतर निर्णय लेने और प्रदर्शन होगा।
- कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) पोर्टल की परिकल्पना और निर्माण तीन हितधारकों अर्थात् संसद सदस्य (MP), केंद्रीय मंत्रालयों और MPA को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए किया गया है।
- नेशनल युथ पार्लियामेंट स्कीम (NYPS) पोर्टल 2.0 का उद्देश्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के बावजूद सभी नागरिकों के लिए इसे खोलकर भागीदारी को बढ़ाना है।
- केंद्रीय मंत्री ने EMRS के छात्रों के लिए नेशनल युथ पार्लियामेंट कम्पटीशन (NYPS) की एक नई योजना भी का शुभारंभ किया है।

21. दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा हाल ही में (सितंबर'24 में) दूरसंचार लाइसेंसों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) DoT ने प्रायोगिक लाइसेंस, प्रदर्शन लाइसेंस और उपकरण प्रकार अनुमोदन (ETA) जारी करने की अपनी प्रक्रियाओं को संशोधित किया है।

B) अंतर-मंत्रालयी परामर्श (IMC) की आवश्यकता नहीं वाले मामलों के लिए, प्रदर्शन लाइसेंस 15 दिनों के बाद स्वीकृत माने जाएंगे।

C) लाइसेंस-एक्सेम्प्ट वायरलेस डिवाइस के लिए ETA के सभी आवेदन अब स्व-घोषणा के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल C
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

संचार मंत्रालय (MoC) के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए **प्रायोगिक लाइसेंस, प्रदर्शन लाइसेंस** और उपकरण प्रकार अनुमोदन (ETA) जारी करने की अपनी प्रक्रियाओं को संशोधित किया है।

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की सिफारिशों के आधार पर ये परिवर्तन, समय की देरी को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और दूरसंचार क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखते हैं।
- अंतर-मंत्रालयी परामर्श (IMC) की आवश्यकता नहीं वाले मामलों के लिए, यदि कोई निर्णय नहीं बताया जाता है तो लाइसेंस 30 दिनों के बाद जारी माना जाएगा।
- IMC के बिना, लाइसेंस 15 दिनों के बाद प्रदान किए गए माने जाएंगे।
- लाइसेंस-एक्सेम्प्ट वायरलेस डिवाइस के लिए ETA के सभी आवेदन अब स्व-घोषणा के आधार पर दिए जाते हैं।
- आवेदक SARAL संचार (पंजीकरण और लाइसेंस के लिए सरलीकृत आवेदन) पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और सफलतापूर्वक जमा करने पर ETA प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

22. किस राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा बनाई जाएगी?

- 1)ओडिशा
- 2)गोवा
- 3)उत्तर प्रदेश
- 4)मध्य प्रदेश
- 5)राजस्थान

उत्तर- 1)ओडिशा

स्पष्टीकरण:

ओडिशा के मुख्यमंत्री (CM) मोहन चरण माझी ने **620 करोड़ रुपये** के निवेश से भुवनेश्वर (ओडिशा) के इन्फोवैली में EMC पार्क में बनने वाली **भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड** विनिर्माण सुविधा के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता की।

- इस परियोजना को मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित **RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (पूर्व में रटनशा इंटरनेशनल रेक्टिफायर लिमिटेड) द्वारा विकसित किया गया था।
- इस सुविधा में निर्मित उत्पादों को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाएगा और रक्षा, परिवहन, एयरोस्पेस और सतत ऊर्जा जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाएगा।

23. किस मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय सामाजिक गतिशीलता अभियान 'स्वच्छता ही सेवा (DDWS)-2024' आयोजित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) के साथ भागीदारी की है?

- 1)स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- 2)विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 3)आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
- 4)महिला और बाल विकास मंत्रालय
- 5)शिक्षा मंत्रालय

उत्तर- 3)आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

स्वच्छता ही सेवा (SHS)-2024, वार्षिक राष्ट्रीय सामाजिक लामबंदी अभियान, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक "स्वभाव स्वच्छता- संस्कार स्वच्छता" विषय के साथ मनाया जा रहा है।

यह अभियान पेयजल & स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) और आवास & शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

- **SHS 2024** का **विषय** स्वच्छता को दैनिक आदत के रूप में बढ़ावा देना है। SHS 2024 का **उद्देश्य** मेगा स्वच्छता अभियान, गंदे और कठिन कचरा स्थलों (ब्लैक स्पॉट) को साफ करने और स्वच्छता कार्यकर्ताओं की पहचान में बड़े पैमाने पर वकालत और नागरिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करना है।
- 4S अभियान के **3 प्रमुख स्तंभ, स्वच्छता की भागीदारी** (स्वच्छता में जन भागीदारी और जागरूकता), **संपूर्ण स्वच्छता** (मेगा स्वच्छता अभियान और स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTU) का परिवर्तन), और **सफाई मित्र सुरक्षा शिविर** (स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा शिविर) हैं।
- SHS अभियान 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो स्वच्छ भारत दिवस (SBD) का अग्रदूत रहा है, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

24. हाल ही में (सितंबर'24 में) किस इंस्टिट्यूट को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूट (PFI) के रूप में अधिसूचित किया गया है?

- 1) इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 - 2) नेशनल हाउसिंग बैंक
 - 3) नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 - 4) पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 - 5) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट
- उत्तर- 5) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट

स्पष्टीकरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA), भारत सरकार (GoI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 2 के तहत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) को पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूट (PFI) के रूप में अधिसूचित किया।

- NaBFID भारत में एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टिट्यूट (DFI) है।
- यह पदनाम NaBFID को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद करेगा, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मजबूत करने में मदद करेगा।
- NaBFID की स्थापना **2021** में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत DFI के रूप में की गई थी।

25. हाल ही में (सितंबर'24 में) किस संगठन ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH) को प्रकार प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में मंजूरी दी है?

- 1) क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया
- 2) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
- 3) एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
- 4) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज
- 5) इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन

उत्तर- 1) क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH), उत्तरी क्षेत्र (NR), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (UP), को UAS प्रमाणन योजना के तहत **ड्रोन** या मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) के प्रकार प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा अनंतिम रूप से मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह भारत में ड्रोन को प्रमाणित करने वाला पहला सरकारी निकाय बन गया है।

- NTH 1.5 लाख रुपये के प्रतिस्पर्धी शुल्क पर ड्रोन प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करता है, जो उद्योग में सबसे कम है, जो भारत की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" (सेल्फ-रीलाइएंट इंडिया) पहलों का समर्थन करता है।
- NTH, 1912 में स्थापित, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MOCA, F&PD) के अधीन है।
- QCI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

26. सितंबर 2024 में, वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद ने कैसर की दवाएँ ट्रेस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमार्टिनिब और डर्वालुमाब पर GST दर को घटाकर _____ कर दिया।

- 1)12%
- 2)16%
- 3)28%
- 4)5%
- 5)18%

उत्तर- **4)5%**

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्री **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्रालय (MoF) की अध्यक्षता में **54वीं** वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की बैठक 9 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली, दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई।

- GST परिषद की कई सिफारिशों में से सबसे उल्लेखनीय **कैसर की दवाओं** ट्रेस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमार्टिनिब और डर्वालुमाब पर GST दर को **12% से घटाकर 5%** करना था।
- GST परिषद ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (RMPU) एयर कंडीशनिंग मशीनों को **HSN 8415** के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और इस पर **28%** की GST दर लागू होगी।
- GST परिषद ने B2B लेनदेन के ई-इनवॉइसिंग के सफल कार्यान्वयन के बाद, व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) ई-इनवॉइसिंग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की सिफारिश की। इसे चुनिंदा क्षेत्रों और राज्यों में स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया जाएगा।
- 15 सितंबर 2024 को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों पर GST दर का सुझाव देने के लिए **13 सदस्यीय** मंत्री समूह (GoM) का गठन किया। इसने GoM को **30 अक्टूबर, 2024** तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें](#)

संशोधित GST दरों वाली वस्तुओं की सूची:

क्रम संख्या	वस्तुओं का नाम	पिछली GST दर	नई GST दर
1.	कैसर की दवाएँ ट्रेस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमार्टिनिब और डर्वालुमाब	12%	5%
2.	स्वादिष्ट सैक्स	18%	12%
3.	धातु स्क्रेप	18%	12%
4.	कार सीटें	18%	28%

27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है?

- 1) नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
- 2) श्री विजयपुरम
- 3) भरतपुर
- 4) अटल नगर
- 5) स्वराज द्वीप

उत्तर- 2) श्री विजयपुरम

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्री **अमित शाह**, गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी **पोर्ट ब्लेयर** का नाम बदलकर '**श्री विजयपुरम**' किया जाएगा।

- श्री विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जीत और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंडमान अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता, प्रचुर समुद्री जीवन, वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है जो 836 द्वीपों, टापुओं और चट्टानों में फैले हुए हैं।
- जनवरी 2023 में, अंडमान द्वीप समूह के एक द्वीप रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया।
- 2018 में, अंडमान के नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया।

28. किस लाइफस्टाइल ब्रैंड ने हाल ही में (सितंबर'24 में) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भारत की कारीगर विरासत को सशक्त बनाने के लिए MSME मंत्रालय के साथ सहयोग किया है?

- 1) मान्यवर
- 2) एलन सोली
- 3) रेमंड
- 4) फैबइंडिया
- 5) AJIO

उत्तर- 4) फैबइंडिया

स्पष्टीकरण:

भारत के अग्रणी लाइफस्टाइल ब्रैंड **फैबइंडिया लिमिटेड** ने प्रधानमंत्री (PM) विश्वकर्मा योजना के तहत भारत की कारीगर विरासत को सशक्त बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के साथ सहयोग किया है।

- पहल का उद्देश्य भारत के पारंपरिक कारीगरों जैसे कुम्हार, बढ़ई, नाव निर्माता, बुनकर, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले और अन्य कुशल कारीगरों की आजीविका को बढ़ाना, उनके उत्पादों को बढ़ावा देना और उनकी बाजार पहुंच का विस्तार करना है।
- फैबइंडिया कारीगरों को अपने उत्पादों की व्यावसायिक अपील बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन रुझानों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनकी शिल्प कौशल में सुधार करने में मदद करेगा।
- PM विश्वकर्मा योजना एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है, जिसे 17 सितंबर, 2023 को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

29. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (BWM) नियम, 2022 के उल्लंघन को दंडित करने के लिए सख्त पर्यावरण मुआवजा (EC) दिशानिर्देश पेश किए हैं?

- 1) ऊर्जा और संसाधन संस्थान
- 2) ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
- 3) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

4)केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5)राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान

उत्तर- 4)केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्पष्टीकरण:

10 सितंबर 2024 को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (BWM) नियम, 2022 के उल्लंघन को दंडित करने के लिए सख्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) दिशानिर्देश पेश किए हैं।

- **उद्देश्य:** पूरे देश में उचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना।
- CPCB गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं से EC लगाने और एकत्र करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ERP की कमी से संबंधित गैर-अनुपालन के लिए EC लगाया जाएगा।
- दिशा-निर्देश न केवल बैटरी अपशिष्ट निपटान विनियमों का पालन करने में विफल रहने पर, बल्कि धातु-विशिष्ट विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने पर भी दंड लगाते हैं।
- BWM नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क EC के बराबर है, जो पहली चूक के लिए **20,000 रुपये** निर्धारित है। यह दूसरी चूक के लिए दोगुना होकर **40,000 रुपये** और तीसरी चूक के लिए **80,000 रुपये** हो जाता है।
- यदि समय सीमा के **एक महीने के भीतर** जमा किया जाता है, तो प्रारंभिक राशि पर **12%** का वार्षिक ब्याज लगेगा। **एक महीने के बाद** लेकिन तीन महीने के भीतर किए गए जमा पर **24%** वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।

30. विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में (सितंबर'24 में) भारत और _____ के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्मारक टिकट जारी किए हैं।

1)रोमानिया

2)हंगरी

3)भूटान

4)नेपाल

5)मंगोलिया

उत्तर- 1)रोमानिया

स्पष्टीकरण:

17 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय (MEA), केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्रालय (MoC), और भारत में रोमानिया के राजदूत डेनिएला-मारियाना सेज़ोनोव ने भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के **75 साल** पूरे होने का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली (दिल्ली) में **भारत-रोमानिया संयुक्त स्मारक टिकट** जारी किए।

- यह आयोजन **राजनयिक द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ** और उनकी **व्यापक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ** के अवसर पर मनाए जा रहे व्यापक समारोहों का हिस्सा है।
- भारत और रोमानिया ने **1948** में राजनयिक संबंध स्थापित किए और 1968 में इसे राजदूत स्तर तक बढ़ा दिया।
- व्यापक साझेदारी स्थापित करने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर की 10वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए एक संयुक्त घोषणा फरवरी 2024 में जारी की गई।

31. 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की दो छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें Bio-RIDE नामक एक योजना के रूप में विलय कर दिया गया है, जिसमें बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री नामक एक नया घटक शामिल है।

B) 79,156 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है।

C) चंद्रयान-3 मिशन जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रौद्योगिकियों को इकट्ठा करना और उनका मूल्यांकन करना और चंद्रमा के नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 1)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

18 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

i. एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें।

ii. Bio-RIDE योजना बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास का समर्थन करेगी।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) की दो छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें एक योजना- 'बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (Bio-RIDE)' के रूप में विलय कर दिया गया है, जिसमें बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री नामक एक नया घटक शामिल है।

- योजना के **तीन** व्यापक घटक: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), इंडस्ट्रियल & एन्तेप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (I&ED), बायोमैनुफैक्चरिंग एंड बायोफाउंड्री हैं।

iii. 5 वर्षों के लिए 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान।

- बजट भाषण 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार, इसमें लगभग **63,000** गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।

iv. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की योजनाओं को जारी रखना।

- 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान **2025-26** तक कुल वित्तीय परिव्यय **35,000 करोड़ रुपये** होगा।

v. चंद्रयान-4 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करेगा।

- चंद्रयान-4** मिशन वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतरने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा।

vi. वीनस की खोज और अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) का विकास।

vii. भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) का विकास के लिए कुल परिव्यय **8240.00 करोड़ रुपये** है।

viii. **11,170 करोड़ रुपये** के अतिरिक्त निधी के साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की पहली इकाई का निर्माण।

ix. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) की स्थापना।

x. फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों पर RABI सीजन 2024 (01.10.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करना। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

32. किस संगठन को हाल ही में (सितंबर'24 में) राजस्थान में माही बांसवाड़ा परियोजना को संभालने और भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने की मंजूरी मिली है?

- 1) भारत संचार निगम लिमिटेड
- 2) रेल विकास निगम लिमिटेड
- 3) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- 4) अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
- 5) भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर

उत्तर- 4) अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (DAE), भारत सरकार (GoI) ने स्वदेशी प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWR) प्रौद्योगिकी पर आधारित राजस्थान के माही बांसवाड़ा में **4x700** मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe) माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (MBRAPP) को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) से अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (ASHVINI) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

- ASHVINI NPCIL (51%) और NTPC लिमिटेड (जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (49%) के नाम से जाना जाता था) के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।
- ASHVINI को मौजूदा विधायी ढांचे के तहत भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- यह संयुक्त JV भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता के तीव्र विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को संयोजित करेगा, ताकि **2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्यों** को पूरा किया जा सके।
- भारत ने 2031-32 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8,180 MW से बढ़ाकर 22,800 MW करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

33. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर, ओडिशा में 'अमृत कतला' लॉन्च किया है?

- 1) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- 2) बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
- 3) जल शक्ति मंत्रालय
- 4) संस्कृति मंत्रालय
- 5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

उत्तर- 1) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के मंत्री **राजीव रंजन सिंह** (ललन सिंह) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय मीठेपानी की जलीय कृषि संस्थान (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर, ओडिशा में मीठे पानी की मछली कतला (लेबियो कतला) की एक नई आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्म 'अमृत कतला' लॉन्च की है।

- अमृत कतला को नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) के उत्तरा (ओडिशा) स्थित नेशनल फ्रेशवाटर फिश ब्रूड बैंक (NFFBB) को दिया गया, जिससे पूरे भारत में किसानों को इसकी व्यापक उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित हुआ।
- अमृत कतला परियोजना को 16 जुलाई, 2024 को **96वें ICAR स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस** पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई और 1 अगस्त, 2024 को औपचारिक रूप से 'CIFA-अमृत कतला' के रूप में ट्रेडमार्क किया गया।

34. किस राज्य ने हाल ही में (सितंबर '24 में) 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने का फैसला किया है?

- 1)केरल
- 2)कर्नाटक
- 3)असम
- 4)मध्य प्रदेश
- 5)तेलंगाना

उत्तर- 5) तेलंगाना

स्पष्टीकरण:

तेलंगाना राज्य सरकार ने हर साल 17 सितंबर को **तेलंगाना प्रजा पालन दिवस** (लोगों के शासन का दिन) के रूप

- 17 सितंबर वह दिन है जिस दिन **1948** में ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई के बाद **हैदराबाद** का भारतीय संघ में **विलय** हुआ था।
- इससे पहले, भारत सरकार (GoI) ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।

35. हाल ही में (सितंबर'24 में) कौन सा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ज्ञांस्कर महोत्सव मनाता है?

- 1)पुडुचेरी
- 2)चंडीगढ़
- 3)उत्तर प्रदेश
- 4)छत्तीसगढ़
- 5)लद्दाख

उत्तर- 5) लद्दाख

स्पष्टीकरण:

लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (**UT**) के उपराज्यपाल (**LG**) ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ने प्रथम महिला नीलम मिश्रा के साथ मिलकर लद्दाख के ज्ञांस्कर उप-मंडल के **सान्नी** में ज्ञांस्कर क्षेत्र की समृद्ध विरासत और परंपराओं के सम्मान के लिए समर्पित दो दिवसीय मेगा महोत्सव **9वें लद्दाख ज्ञांस्कर महोत्सव 2024** का उद्घाटन किया।

- यह महोत्सव लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् (LAHDC), कारगिल, पर्यटन और संस्कृति विभाग, लद्दाख और कारगिल, लद्दाख के जिला प्रशासन द्वारा 13 और 14 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था।
- ज्ञांस्कर को आधिकारिक तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद से 2024 ज्ञांस्कर महोत्सव **पहला उत्सव** है।

36. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) भारतीय EEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) का एकीकृत महासागर ऊर्जा मानचित्रावली विकसित किया है?

- 1)वर्ल्ड मेट्रोलाॉजिकल आर्गेनाइजेशन
- 2)इंटरनेशनल हयड्रोग्राफिक आर्गेनाइजेशन
- 3)इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफार्मेशन सर्विसेज
- 4)नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च
- 5)इंडियन ओशन ऑब्सेर्विंग सिस्टम

उत्तर- 3)इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफार्मेशन सर्विसेज

स्पष्टीकरण:

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (**MoES**) के सचिव **डॉ M रविचंद्रन** ने भारतीय **EEZ** (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के एकीकृत महासागर ऊर्जा मानचित्रावली को लॉन्च किया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (**INCOIS**) की एक अग्रणी पहल है, जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (**ESSO**) की एक इकाई और MoES के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

- एकीकृत महासागर ऊर्जा मानचित्रावली भारत के EEZ के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करता है।

- यह उच्च ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, जो नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है।
- मानचित्रावली भारतीय EEZ के भीतर 5 क्षेत्रों के लिए 9.2 लाख टेरावाट-घंटे (TWh) वार्षिक महासागर ऊर्जा का अनुमान लगाता है।

37. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहक व्यक्तिगत वित्तीय जरूरत के लिए अपने भविष्य निधि (PF) खातों से 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं?

- 1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- 2) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
- 3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- 4) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- 5) वित्त मंत्रालय

उत्तर- 4) श्रम और रोजगार मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

17 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री डॉ. **मनसुख मंडाविया**, श्रम & रोजगार मंत्रालय (**MoL&E**) ने घोषणा की कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (**EPFO**) के ग्राहक व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों के लिए अपने भविष्य निधि (PF) खातों से **1 लाख रुपये तक** निकाल सकते हैं, जो मौजूदा सीमा 50,000 रुपये से अधिक है।

- उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन कर्मचारियों ने वर्तमान नौकरी में **6 महीने** पूरे नहीं किए हैं, वे अब राशि निकालने के पात्र हैं, जो पहले प्रतिबंधित थी।
- उन्होंने बताया कि भारत सरकार (GoI) वर्तमान में EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (**ESIC**) के तहत आय सीमा को मौजूदा **15,000 रुपये** प्रति माह और **21,000 रुपये** से बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।
- भारत सरकार (GoI) वर्तमान में EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (**ESIC**) के तहत आय सीमा को मौजूदा **15,000 रुपये** प्रति माह और **21,000 रुपये** से बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

38. किस राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने सितंबर 2024 में अपने पंचायत उपचुनाव के दौरान भारत में पहली बार सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया है?

- 1) छत्तीसगढ़
- 2) राजस्थान
- 3) उत्तर प्रदेश
- 4) मध्य प्रदेश
- 5) महाराष्ट्र

उत्तर- 4) मध्य प्रदेश

स्पष्टीकरण:

मध्य प्रदेश (MP) राज्य चुनाव आयोग (**SEC**) ने भारत में **पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया** आयोजित की। इसे **भोपाल (MP)** में बैरसिया तहसील के **रतुआ रतनपुर** गांव में **सरपंच** पद के लिए हुए **पंचायत उपचुनाव** के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था और इसमें 84% मतदान हुआ था।

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के मैनुअल हिस्सों को कंप्यूटरीकृत करना है जो पहले कागज पर किए जाते थे।
- नई प्रणाली मतदाता पहचान के लिए अंगूठे के निशान और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करती है, प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है और प्रॉक्सी वोटिंग को खत्म करती है।

39. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) SISA इनफार्मेशन सिक््योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर सर्टिफाइड सिक््योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (CSPAI) कार्यक्रम शुरू किया है?

- 1) इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम
- 2) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग
- 3) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स
- 4) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च
- 5) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर

उत्तर- 1) इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम

स्पष्टीकरण:

23 सितंबर, 2024 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम (CERT-In) ने SISA इनफार्मेशन सिक््योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से, सर्टिफाइड सिक््योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (CSPAI) प्रोग्राम शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला ANSI नेशनल एकेडिटेशन बोर्ड (ANAB) एकेडिटेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा प्रमाणन है।

- कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा पेशेवरों को टिकाऊ और सुरक्षित प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए व्यावसायिक अनुप्रयोगों में AI को एकीकृत करने के ज्ञान से लैस करना है।

40. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) नई दिल्ली, दिल्ली में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है?

- 1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- 2) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
- 3) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- 4) शिक्षा मंत्रालय
- 5) गृह मंत्रालय

उत्तर- 1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

24 सितंबर 2024 को, केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) प्रतापराव गणपतराव जाधव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने नई दिल्ली, दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक हाइब्रिड कार्यक्रम में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0' के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

- अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
- लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने भारत भर के चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निषेध केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- यह अभियान 60 दिनों तक चलेगा और इसमें शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने, प्रवर्तन अभियान और सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों जैसी पहलों को बढ़ावा देने और तंबाकू मुक्त गांवों की स्थापना आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- यह अभियान 7 मंत्रालयों के बीच साझेदारी और समन्वय को बढ़ावा देकर 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है
- कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने तंबाकू मुक्त रहने के लिए 'से नो टू टोबैको' की शपथ ली।
- कार्यक्रम के दौरान, 3 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अर्थात् स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाइड, गांवों को तंबाकू मुक्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून लागू करने वालों के लिए दिशा-निर्देश लॉन्च किए गए। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

41. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर '24 में) लॉजिस्टिक्स उद्योग में चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) हैकथॉन 2.0 लॉन्च किया है?

- 1) NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड
- 2) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
- 3) इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
- 4) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
- 5) नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन

उत्तर- 1) NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

2024 के 25 सितंबर को NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) ने NITI आयोग – अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) लॉजिस्टिक्स हैकथॉन 2.0 की शुरुआत की, जिसमें **राजीव सिंह ठाकुर**, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के अतिरिक्त सचिव, ने नई दिल्ली, दिल्ली में वाणिज्य भवन में आयोजन किया।

- इस प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल समाधान तैयार करना है।
- कार्यक्रम के दौरान लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए ULIP द्वारा संचालित ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट (TYT) एप्लिकेशन (ऐप) भी लॉन्च किया गया।
- ULIP लॉजिस्टिक्स हैकथॉन 2.0 दिसंबर 2021 में पहले संस्करण की सफलता पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान सामने आए।
- ULIP प्रधानमंत्री गति शक्ति (नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी) के तहत प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है।

42. किस संगठन/मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर '24 में) ट्रेन दुर्घटनाओं का जवाब देने और बचाव अभियान चलाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे (NWR) क्षेत्र में रेल रक्षक दल की स्थापना की है।

- 1) गृह मंत्रालय
- 2) भारतीय रेलवे
- 3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 4) रक्षा मंत्रालय
- 5) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम

उत्तर- 2) भारतीय रेलवे

स्पष्टीकरण:

24 सितंबर 2024 को, भारतीय रेलवे ने पहली बार **उत्तर पश्चिमी रेलवे (NWR)** क्षेत्र में एक पायलट परियोजना के तहत **रेल रक्षक दल** की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं का तुरंत जवाब देना और बचाव अभियान चलाना है।

- रेल रक्षक दल का प्राथमिक लक्ष्य रेलवे को सहायता प्रदान करना और आपात स्थिति के समय जिला प्रशासन का समर्थन करना है।
- रेल रक्षक दल का गठन केंद्रीय मंत्री **अश्विनी वैष्णव**, रेल मंत्रालय की प्रत्यक्ष देखरेख में किया गया है।
- इस पहल में शारीरिक रूप से स्वस्थ रेलवे कर्मचारियों को तैनात करना, उन्हें तैराकी जैसे कौशल में प्रशिक्षित करना और आपात स्थिति के दौरान सहायता के लिए हल्के उपकरणों का उपयोग करना शामिल है।

43. हाल ही में (सितंबर'24 में) केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) की प्लेटिनम जुबली मनाने के लिए किसने स्मारक सिक्के का अनावरण किया?

- 1) नरेंद्र मोदी
- 2) गिरिराज सिंह
- 3) एकनाथ शिंदे
- 4) सिद्धारमैया
- 5) अमित शाह

उत्तर- 2) गिरिराज सिंह

स्पष्टीकरण:

20 सितंबर 2024 को, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्रालय (MoT) ने कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) की प्लेटिनम जुबली (75वीं वर्षगांठ) मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के का अनावरण किया।

- केंद्रीय मंत्री ने 'CSB इन द सर्विस ऑफ द नेशन सिंस 1949' शीर्षक से एक कॉफी टेबल बुक और CSB के 75 साल के लोगो वाला एक डाक कवर भी लॉन्च किया।
- स्वतंत्र भारत सरकार ने 20 सितंबर 1948 को CSB अधिनियम 1948 लागू किया।
- क्वाटरनेरी मिश्र धातु (50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता) से बने सिक्के का वजन 35 ग्राम है और इसका व्यास 44 मिलीमीटर (mm) है।
- कार्यक्रम के दौरान चार नई प्रौद्योगिकियों, अर्थात् निर्मूल, सेरी-विन, मिस्टर प्रो और एक ट्रैपिंग मशीन का अनावरण किया गया।
- कार्यक्रम के दौरान, CSB ने रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहकारी प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFRI) बैरकपुर, पश्चिम बंगाल (WB), बेंगलुरु में जैन विश्वविद्यालय और जोरहाट (असम) में असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU) जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया।
- कार्यक्रम के दौरान सिल्क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SMOI) की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई।
- वस्त्र मंत्रालय (MoT) ने चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को अधिसूचित किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाला है।
- 10 अगस्त 2024 को वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने गुजरात के पालनपुर के सरदारकृषिणगर में एरी रेशम उत्पादन प्रोत्साहन परियोजना का शुभारंभ किया। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

44. उस सुपरकंप्यूटर का नाम क्या है जिसे हाल ही में (सितंबर'24 में) प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था?

- 1) PARAM सिद्धि
- 2) PARAM शिवाय
- 3) PARAM रुद्र
- 4) PARAM उत्कर्ष
- 5) PARAM प्रवेश

उत्तर- 3) PARAM रुद्र

स्पष्टीकरण:

26 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 130 करोड़ रुपये के 3 'PARAM रुद्र' सुपरकंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। इन सुपरकंप्यूटरों को नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

- इन सुपरकंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान प्रदान करने के लिए नई दिल्ली (दिल्ली), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल, WB) में तैनात किया गया है।
- पुणे स्थित ग्रेट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपरकंप्यूटर का लाभ उठाएगा।
- भारत सरकार (GoI) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए केंद्रीय बजट में **1 लाख करोड़ रुपये** के अनुसंधान कोष की घोषणा की है।
- 26 सितंबर 2026 को, PM नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा अधिग्रहित मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (HPC) सिस्टम का उद्घाटन किया।
- यह परियोजना **850 करोड़ रुपये** के निवेश से विकसित की गई है, जो मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए भारत की अभिकलनात्मक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

45. हाल ही में (सितंबर'24 में) इंडियन एयर फोर्स (IAF) की 18 फ्लाईंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं?

1)सुभाश्री श्रीराम

2)रेखा शर्मा

3)अंजलि गुप्ता

4)मोहना सिंह

5)ज्योति विज

उत्तर- 4)मोहना सिंह

स्पष्टीकरण:

स्क्वाड्रन लीडर **मोहना सिंह** इंडियन एयर फोर्स (IAF) की **18 फ्लाईंग बुलेट्स स्क्वाड्रन**, जो भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) **तेजस फाइटर जेट** का संचालन करती है, में शामिल होने वाली **पहली महिला फाइटर पायलट** बन गई हैं। फ्लाईंग बुलेट्स स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात सेक्टर में नलिया एयर बेस पर तैनात है।

- मोहना सिंह स्क्वाड्रन लीडर **भावना कंठ** और **अवनी चतुर्वेदी** के साथ 2016 में IAF में कमीशन की गई **पहली 3 महिला फाइटर पायलटों** में से एक थीं।
- उन्होंने 2019 में दिन के उजाले में "हॉक" एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली IAF की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया।
- 2020 में अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ के साथ उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

INTERNATIONAL AFFAIRS

1. किस संगठन ने हाल ही में (अगस्त'24 में) अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के 10 देशों में आपात स्थितियों के गंभीर अल्पपोषण के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं?

1)संयुक्त राष्ट्र

2)एशियाई विकास बैंक

3)ड्यूश बैंक AG

4)विश्व बैंक

5)अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

उत्तर- 1)संयुक्त राष्ट्र

स्पष्टीकरण:

30 अगस्त, 2024 को, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के 10 देशों में मानवीय आपात स्थितियों में गंभीर रूप से कम फंडिंग से निपटने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष (CERF), UN वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए।

- फरवरी 2024 में 7 देशों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करने के बाद, यह 2024 के लिए कम वित्त पोषित आपात स्थितियों के लिए CERF का दूसरा आवंटन है।
- यह कोष यमन (20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और इथियोपिया (15 मिलियन अमेरिकी डॉलर) में सहायता कार्यों का समर्थन करेगा, जहाँ लोग भूख, विस्थापन, बीमारी और जलवायु आपदाओं के जटिल संकटों का सामना कर रहे हैं।
- अन्य आवंटनों में म्यांमार (12 मिलियन अमेरिकी डॉलर), माली (11 मिलियन अमेरिकी डॉलर), बुर्किना फासो (10 मिलियन अमेरिकी डॉलर), हैती (9 मिलियन अमेरिकी डॉलर), कैमरून (7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और मोजाम्बिक (7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।
- अल नीनो-प्रेरित सूखे और बाढ़ का जवाब देने वाले देश, जैसे बुरुंडी (5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और मलावी (4 मिलियन अमेरिकी डॉलर), को भी अतिरिक्त धनराशि मिली।

2. किस देश और भारत ने हाल ही में (सितंबर '24 में) अपने वित्तीय और पेशेवर सेवा सहयोग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है?

- 1)नेपाल
- 2)पेरू
- 3)यूनाइटेड किंगडम
- 4)अज़रबैजान
- 5)स्पेन

उत्तर- 3)यूनाइटेड किंगडम

स्पष्टीकरण:

यूनाइटेड किंगडम (UK) और भारत ने UK-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB) लॉन्च किया है, जो उनके वित्तीय और पेशेवर सेवा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल है।

- UKIIFB समझौते पर सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के बीच लंदन, UK में हस्ताक्षर किए गए।
- यह पहल भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश को आकर्षित करने के लिए परियोजना नियोजन और चरणबद्धता में UK की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है।

3. हाल ही में (सितंबर '24 में) किस देश को BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का नया सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है?

- 1)अर्जेंटीना
- 2)भारत
- 3)स्पेन
- 4)अल्जीरिया
- 5)बेल्जियम

उत्तर- 4)अल्जीरिया

स्पष्टीकरण:

अल्जीरिया को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (BRICS) देशों द्वारा स्थापित एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक (MDB), BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), का नया सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी घोषणा NDB की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने 29 से 31 अगस्त 2024 तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित NDB की 9वीं वार्षिक बैठक के दौरान की।

- बैठक का विषय "इन्वेस्टिंग इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर" है

- इस सदस्यता के साथ, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद अल्जीरिया NDB के साथ एकीकृत होने वाला **तीसरा अरब देश** बन गया।
- NDB का उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों (EMDC) में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।

4. हाल ही में (सितंबर '24 में) कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है?

- 1) स्पेन
 - 2) नेपाल
 - 3) पैराग्वे
 - 4) नॉर्वे
 - 5) बांग्लादेश
- उत्तर- 2) नेपाल

स्पष्टीकरण:

नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला **101वाँ देश** बन गया है। नई दिल्ली, दिल्ली में एक बैठक के दौरान नेपाल के Charge d' affairs **डॉ. सुरेंद्र थापा** और भारत के MEA में संयुक्त सचिव आर्थिक कूटनीति बहुपक्षीय आर्थिक संबंध (ED&MER) **अभिषेक सिंह** के बीच अनुसमर्थन के साधन का आदान-प्रदान किया गया।

- जून 2024 में, **पैराग्वे** ISA का 100वाँ पूर्ण सदस्य बन गया।
- ISA की स्थापना **2015** में भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।

5. अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के साथ साझेदारी में किस संगठन ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में योगदान में तेजी लाने के लिए दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश लॉन्च किए हैं?

- 1) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
- 2) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
- 3) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- 4) संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन
- 5) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

उत्तर- 3) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

स्पष्टीकरण:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में योगदान को बढ़ाने के लिए **दुनिया के पहले** अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश '**ISO/UNDP PAS 53002**' जारी किए हैं।

- कोलंबिया के **Cartagena de Indias** में आयोजित ISO वार्षिक बैठक 2024 में दिशा-निर्देश पेश किए गए।
- यह संगठनों को अपने मुख्य संचालन में SDG को शामिल करने और उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है।
- वे वैश्विक स्तर पर, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में **सभी प्रकार** और आकार के संगठनों पर लागू होते हैं।

6. इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एथिक्स (ICAIRE) को सऊदी अरब के रियाद में तीसरे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन के दौरान _____ के तहत श्रेणी 2 (C2) केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था?

- 1) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
- 2) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

- 3)संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
 - 4)व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
 - 5)संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
- उत्तर- 5)संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

स्पष्टीकरण:

सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी (SDAIA) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने रियाद, सऊदी अरब में 10-12 सितंबर, 2024 तक आयोजित तीसरे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन के दौरान UNESCO के तहत **श्रेणी 2 (C2)केंद्र** के रूप में इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एथिक्स (ICAIRE) के वर्गीकरण की घोषणा की।

- यह AI एथिक्स में सऊदी अरब के नेतृत्व और UN सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- यह वर्गीकरण AI एथिक्स, पॉलिसीस और रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

7. उस देश का नाम बताइए जो हाल ही में (सितंबर'24 में) कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है।

- 1)बेलीज
- 2)जॉर्डन
- 3)जमैका
- 4)ब्राजील
- 5)काबो वर्डे

उत्तर- 2)जॉर्डन

स्पष्टीकरण:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक तौर पर **जॉर्डन** को **कुष्ठ रोग** (जिसे हैनसेन रोग भी कहा जाता है) को **समाप्त करने वाले** दुनिया के **पहले देश** के रूप में सत्यापित किया है, जो एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होने वाली एक पुरानी संक्रामक बीमारी है।

- जॉर्डन ने 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग के किसी भी स्थानीय रूप से प्रसारित (स्वदेशी) मामले की सूचना नहीं दी है। इस उपलब्धि को दुनिया भर में कुष्ठ रोग को समाप्त करने के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
- इस उपलब्धि से अन्य देशों को कुष्ठ रोग के खिलाफ अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।
- कुष्ठ रोग एक पुरानी बीमारी है जो मुख्य रूप से त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ के म्यूकोसा और आंखों को प्रभावित करती है।

8. हाल ही में (सितंबर'24 में) किस देश ने 2024-2027 कार्यकाल के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (ASOSAI) की अध्यक्षता संभाली?

- 1)संयुक्त राज्य अमेरिका
- 2)भारत
- 3)हंगरी
- 4)बांग्लादेश
- 5)चीन

उत्तर- 2)भारत

स्पष्टीकरण:

24 सितंबर 2024 को, **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) ने 2024-2027 कार्यकाल** के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन (ASOSAI) की **अध्यक्षता** संभाली।

- **गिरीश चंद्र मुर्मू** अगस्त 2020 से भारत के 14वें CAG के रूप में कार्यरत हैं।
- भारत के CAG द्वारा आयोजित ASOSAI की 16वीं सभा 21 से 27 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- 6 सितंबर 2024 को हनोई, वियतनाम में आयोजित ASOSAI के गवर्निंग बोर्ड की 56वीं बैठक में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को **ASOSAI की 16वीं सभा (2024)** का मेजबान और 2024-2027 तक ASOSAI का अध्यक्ष चुना गया।
- 23 सितंबर 2024 को, 60वीं ASOSAI गवर्निंग बोर्ड बैठक नई दिल्ली में हुई।
- सामान्य लेखापरीक्षा न्यायालय (GCA) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए **सऊदी अरब** को 2027-2030 के कार्यकाल के लिए ASOSAI का अध्यक्ष चुना गया है। सऊदी अरब को 17वीं ASOSAI आम सभा की मेजबानी के रूप में भी चुना गया। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

9. हाल ही में (सितंबर'24 में) कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल हुआ है?

- 1) भारत
 - 2) कुराकाओ
 - 3) जर्मनी
 - 4) बांग्लादेश
 - 5) सिंगापुर
- उत्तर- **1) भारत**

स्पष्टीकरण:

20 सितंबर 2024 को, **भारत** औपचारिक रूप से IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल हो गया।

- IBCA भारत द्वारा बिग कैट्स और उनके प्राकृतिक आवासों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थापित एक वैश्विक पहल है।
- इसके साथ ही, **4 देश (भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया)** अब **IBCA के सदस्य** बन गए हैं।
- IBCA को PM मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय में "कमेमोरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडियास **प्रोजेक्ट टाइगर**" कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था।
- फ्रेमवर्क समझौते का उद्देश्य IBCA की स्थापना करना था, ताकि **7 बिग कैट्स** - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आम चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान किया जा सके।
- IBCA का उद्देश्य **95 बिग कैट्स** वाले देशों, बिग कैट्स के संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों का एक बहु-राष्ट्र, बहु-एजेंसी गठबंधन बनाना है।

GOVT SCHEMES

1. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त'24 में) उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) कार्यक्रम शुरू किया है।

- 1) राजस्थान
- 2) असम
- 3) उत्तराखंड

4)ओडिशा

5)बिहार

उत्तर- 4)ओडिशा

स्पष्टीकरण:

ओडिशा सरकार ने ओडिशा में उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) कार्यक्रम शुरू किया है।

- ओडिशा सरकार और शिक्षा मंत्रालय (MoE) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया।
- PM-USHA पहल का उद्देश्य पूरे ओडिशा में उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र की एक प्रमुख पहल है।
- इस पहल के तहत, केंद्र सरकार ओडिशा में उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
- केंद्र आवंटित अनुदान का 60% जारी करेगा, जबकि राज्य 40% वहन करेगा।

2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) द्वारा हाल ही में (अगस्त'24 में) लॉन्च किए गए 'एग्री फंड फॉर स्टार्ट अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज (AgriSURE)' का परिव्यय क्या था?

1)500 करोड़ रुपये

2)1000 करोड़ रुपये

3)750 करोड़ रुपये

4)250 करोड़ रुपये

5)100 करोड़ रुपये

उत्तर- 3)750 करोड़ रुपये

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने नई दिल्ली, दिल्ली में 750 करोड़ रुपये का 'एग्री फंड फॉर स्टार्ट अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज (AgriSURE)' और 'कृषिनिवेश' नामक कृषिनिवेश पोर्टल लॉन्च किया है।

- उन्होंने उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को कृषि अवसंरचना निधि (AIF) उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 भी प्रदान किए।
- 750 करोड़ में से, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने 250-250 करोड़ प्रदान किए, और अन्य 250 करोड़ निजी निवेशकों सहित अन्य संस्थानों से जुटाए जाने हैं।
- यह श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि की श्रेणी के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत है। NABARD की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NABENTURES लिमिटेड, फंड के निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है।
- कृषिनिवेश पोर्टल कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाया गया एक व्यापक मंच है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

3. मध्य प्रदेश (MP) सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए हाल ही में (अगस्त'24 में) कौन सी योजना शुरू की है?

1)NTR भरोसा पेंशन स्कीम

2)मुख्यमंत्री निजुत मोइना

3)वंदावन ग्राम स्कीम

4)इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम

5)रिटेल डायरेक्ट स्कीम

उत्तर- 3)वंदावन ग्राम स्कीम

स्पष्टीकरण:

मध्य प्रदेश (MP) सरकार ने वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्रमशः ग्रामीण विकास को बढ़ाना और MP की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना है।

- MP सरकार ने मराठा मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होल्कर की 320वीं जयंती समारोह की योजना बनाने के लिए एक आयोजन समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
- इस योजना का उद्देश्य गांवों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत दूध संरक्षण और ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 'गौशालाएं (काऊ शेड्स)' स्थापित की जाएंगी।

4. हाल ही में (सितंबर'24 में) प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सूरत, गुजरात में 27 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कौन सी पहल शुरू की गई थी?

- 1) e-FAST इंडिया
 - 2) जटायु कंज़र्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर
 - 3) आत्मनिर्भरता
 - 4) जीवन समर्थ
 - 5) जल संचय जन भागीदारी
- उत्तर- 5) जल संचय जन भागीदारी

स्पष्टीकरण:

6 सितंबर, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में 27 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'जल संचय जन भागीदारी' पहल का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) और गुजरात सरकार के बीच एक सहयोग है, जो जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।

- इस पहल में जल स्थिरता में सुधार के लिए मजबूत सार्वजनिक भागीदारी के साथ गुजरात भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है।
- 'जल संचय जन भागीदारी' का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके पानी की कमी को दूर करना है।
- इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में वर्षा जल संचयन उपायों को लागू करके भूजल स्तर को बढ़ाना और जल घुसपैठ को बढ़ावा देना है।
- भारत, दुनिया के ताजे पानी के केवल 4% के साथ, गंभीर पानी की कमी का सामना कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से बदतर हो गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के संयोजन से इसे संबोधित करना है। यह पहल 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैम्पेन' के साथ संरेखित है।
- जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना को भी जल संरक्षण को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में उजागर किया गया।

5. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स (NPSP) - 2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए एक कार्यक्रम, SAMRIDH योजना का दूसरा कोहोर्ट लॉन्च किया है?

- 1) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - 2) महिला और बाल विकास मंत्रालय
 - 3) संचार मंत्रालय
 - 4) संस्कृति मंत्रालय
 - 5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- उत्तर- 1) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

4 सितंबर 2024 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव S कृष्णन ने उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (SAMRIDH) योजना के लिए MeitY के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के दूसरे कोहोर्ट को लॉन्च किया।

- इस पहल को 6-9 महीने के त्वरण कार्यक्रम, 40 लाख रुपये तक के फंड आदि के साथ शुरुआती चरण के स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया SAMRIDH, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स (NPSP) - 2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए MeitY का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- SAMRIDH का लक्ष्य 5-10 स्टार्टअप के समूह के साथ 3 साल की अवधि में 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप का समर्थन करना है। इस योजना को MSH और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. हाल ही में (सितंबर'24 में) किस मंत्रालय के तहत विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आंध्र प्रदेश में 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है?

1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

2) गृह मंत्रालय

3) नागरिक उड्डयन मंत्रालय

4) संचार मंत्रालय

5) पर्यटन मंत्रालय

उत्तर- 3) नागरिक उड्डयन मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

6 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आंध्र प्रदेश (AP) पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया।

i. उन्होंने इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के 8 अन्य हवाई अड्डों, कोयम्बटूर (तमिलनाडु (TN)), डबोलिम (गोवा), इंदौर (मध्य प्रदेश (MP)), बागडोगरा (पश्चिम बंगाल (WB)), रांची (झारखंड), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़) और भुवनेश्वर (ओडिशा) हवाई अड्डों तक भी वर्चुअली विस्तारित किया है।

ii. डिजी यात्रा सुविधा पहली बार 1 दिसंबर, 2022 को 3 हवाई अड्डों, नई दिल्ली (दिल्ली), वाराणसी (उत्तर प्रदेश, UP) और बेंगलुरु (कर्नाटक) पर शुरू की गई थी।

iii. 9 और नए डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों के लॉन्च के साथ, डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या 15 (पहले चरण में लॉन्च) से बढ़कर 24 हो जाएगी।

iv. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री K. राममोहन नायडू ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के विस्तार की घोषणा की, जिसे 2016 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों को क्षेत्रीय संपर्क प्रदान करना था। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

7. किस राज्य ने भूमिहीन कृषि परिवारों को तीन किस्तों में सालाना 12,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'CM-KISAN योजना' शुरू की?

1) मध्य प्रदेश

2) बिहार

3) ओडिशा

4) हरियाणा

5) कर्नाटक

उत्तर- 3) ओडिशा

स्पष्टीकरण:

8 सितंबर, 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री (CM) मोहन चरण माझी ने राज्य के नुआखाई उत्सव के दौरान ओडिशा के संबलपुर में गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में 'CM-KISAN योजना' शुरू की। वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए, ओडिशा सरकार ने CM-KISAN योजना के लिए 1,935 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

- इस योजना ने 'आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता (KALIA)' योजना की जगह ली है और यह छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को समर्थन देने पर केंद्रित है।
- इस योजना के तहत 46 लाख छोटे और सीमांत किसानों को **925 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता** मिलेगी।
- छोटे और सीमांत किसानों को दो किस्तों (नुआखाई और अक्षय तृतीया पर) में **सालाना 4,000 रुपये** मिलेंगे, भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- भूमिहीन कृषि परिवारों को तीन किस्तों में सालाना **12,500 रुपये** मिलेंगे।
- उन्होंने कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के **कृषक ओडिशा एकीकृत पोर्टल** का भी अनावरण किया।

8. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) किस वर्ष शुरू की गई थी?

- 1)2014
- 2)2015
- 3)2018
- 4)2019
- 5)2020

उत्तर- 4)2019

स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY), एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) जो देश भर में सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, ने सफल कार्यान्वयन के **5 साल** पूरे कर लिए हैं।

- PM-KMY को **12 सितंबर, 2019** को प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में लॉन्च किया था।
- इस योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) द्वारा मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।
- वे SMF जो **18 से 40 वर्ष** की आयु के बीच हैं, वे योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
- सभी पात्र SMF को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पेंशन फंड में **प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये** के बीच राशि का योगदान करना आवश्यक है।
- PM-KMY के तहत, पात्र SMF को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद **3,000 रुपये** की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों।
- LIC इस योजना का **पेंशन फंड मैनेजर** है और लाभार्थी पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (PM-किसान) के माध्यम से किया जाता है।
[अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

9. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) किस वर्ष शुरू की गई थी?

- 1)2015
- 2)2014
- 3)2019
- 4)2020
- 5)2022

उत्तर- 4)2020

स्पष्टीकरण:

11 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री **राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) ने नई दिल्ली, दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की **चौथी** वर्षगांठ पर मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया।

- केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (NFDP) पोर्टल लॉन्च किया, जो मत्स्य पालन क्षेत्र, सूचना सेवाओं, और मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न हितधारकों की रजिस्ट्री के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा, मत्स्य पालन, और मत्स्य पालन से संबंधित सहायता
- पोर्टल **PM-MKSSY** के तहत बनाया गया है, जो PMMSY के तहत शुरू किया गया
- उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समरीदी साहि-योजना (**PM-MKSSY**) के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए
- PM-MKSSY का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देना और मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) का समर्थन करना है, जिसमें 4 वर्षों की अवधि में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24)से FY27 तक भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में **6,000 करोड़ रुपये** से अधिक का कुल निवेश है।
- इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने **3** विशिष्ट मत्स्य पालन -पोषण और प्रसंस्करण समूहों : **मोती की खेती, सजावटी मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल की खेती** की स्थापना की घोषणा की।
- उन्होंने तटीय राज्यों और UT में **100** तटीय गांवों को **क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज (CRCFV)** में विकसित करने के लिए दिशानिर्देशों का भी अनावरण किया।
- 36 राज्यों/UT में से **22** ने या तो अपनी मछली को अपनाया है या घोषित किया है, **3** ने राज्य जलीय पशु घोषित किया है और **लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ** UT ने अपने राज्य पशु घोषित किए हैं, जो समुद्री प्रजातियां हैं।
- 30 अगस्त 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने **364 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक **जलयान संचार & सहायता प्रणाली** का शुभारंभ किया।
- **PMMSY** को PM नरेंद्र मोदी ने **10 सितंबर, 2020** को 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

10. उस योजना का नाम बताइए जिसे हाल ही में (सितंबर'24 में) वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा लॉन्च किया गया था जो नाबालिगों के लिए बचत-सह-पेंशन योजना है।

- 1)श्रमिक बसेरा
- 2)NTR भरोसा
- 3)उपवन योजना
- 4)EMPS 2024
- 5)NPS वात्सल्य

उत्तर- **5)NPS वात्सल्य**

स्पष्टीकरण:

18 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्रालय (MoF) ने नई दिल्ली, दिल्ली में नाबालिगों के लिए बचत-सह-पेंशन योजना 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (**NPS वात्सल्य**)' का शुभारंभ किया।

- NPS वात्सल्य माता-पिता और अभिभावकों को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों का भविष्य बचाने में सक्षम बनाएगा।
- वात्सल्य खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि **1,000 रुपये** है और उसके बाद, ग्राहकों को प्रति वर्ष 1,000 रुपये का योगदान करना होगा।
- यह योजना बच्चों के लिए पहले से मौजूद NPS का ही विस्तार है।
- सभी नाबालिग नागरिक, जो **18 वर्ष (वर्ष) से कम उम्र** के हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही, बच्चे और माता-पिता/अभिभावक दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- यदि खाते में जमा राशि 18 वर्ष की आयु में **2.5 लाख रुपये से अधिक** है, तो उस राशि का 80% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष 20% एकमुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

11. मिजोरम में छोटे उद्यमियों और किसानों को समर्थन और सहायता देने के लिए हाल ही में (सितंबर'24 में) कौन सी योजना शुरू की गई है?

- 1) विज्ञान धारा
- 2) IT सक्षम युवा
- 3) बाना कैह
- 4) लाडका भाऊ
- 5) श्रमिक बसेरा

उत्तर- 3) बाना कैह

स्पष्टीकरण:

19 सितंबर 2024 को, मिजोरम के मुख्यमंत्री (CM) पु लालदुहोमा ने मिजोरम भर में छोटे उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए 'मिजोरम बाना कैह' (हैंडहोल्डिंग) योजना शुरू की है।

- आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- बाना कैह योजना में पांच महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं
- चयनित प्रगति साझेदारों (लाभार्थियों) के लिए वित्तीय सहायता पैकेज, जिसमें साझेदार बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- अपने ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 100% तक के ब्याज अनुदान का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करते हैं।
- सरकार ने वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 में कृषि आश्वासन के लिए प्रदान किए गए 110 करोड़ रुपये के बजट के अलावा, 2024-25 के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

12. किस मंत्रालय ने हाल ही में (सितंबर'24 में) भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली (दिल्ली) में 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है?

- 1) सहकारिता मंत्रालय
- 2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- 3) गृह मंत्रालय
- 4) मत्स्य पालन, पशुपालन & डेयरी मंत्रालय
- 5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

उत्तर- 1) सहकारिता मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

19 सितंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय (MoC) ने नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में MoC द्वारा की गई पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का शुभारंभ किया।

- सम्मेलन के मुख्य सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए "सहकार-से-समृद्धि" विषय के तहत '100 दिनों की पहल' शुरू की, और इससे देश भर के लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है।
- श्वेत क्रांति 2.0 के तहत GoI का मुख्य लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध उत्पादन को 50%, अर्थात् वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से 1,000 लाख लीटर तक बढ़ाना है।
- उन्होंने 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल के लिए एसओपी भी लॉन्च किए, पहल के 3 प्रमुख घटक डेयरी किसानों को रुपये-किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का वितरण, डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (ATM) का वितरण और सहकारी बैंकों में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों का खाता खोलना है।

- केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक पंचायत में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और मजबूती के लिए मार्गदर्शिका (एक्शन प्लान) का शुभारंभ किया है। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।](#)

13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से उभरी कौन सी योजना ने हाल ही में (सितंबर'24 में) अपने सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे किए हैं?

- 1)हर घर जल
 - 2)प्रधानमंत्री जन धन योजना
 - 3)प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
 - 4)मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन
 - 5)आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना
- उत्तर- 5)आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना

स्पष्टीकरण:

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), भारत सरकार (GoI) की एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत (AB) के प्रमुख घटकों में से एक है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से उभरी है, ने सफल कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

- इसे 23 सितंबर, 2018 को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में लॉन्च किया था।
- इस योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- AB PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए सालाना 5 लाख रुपये प्रति परिवार का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है
- यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्चों को कवर करती है, जिसमें निदान और दवाओं का खर्च शामिल है।
- 11 सितंबर 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हुए AB PM-JAY के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
- 9 सितंबर 2024 तक, 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज मिला है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

VISITS

1. 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

- A)PM मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के पास वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी।
- B)PM मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का भी शुभारंभ किया।
- C)PM मोदी ने मुंबई, महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित चौथे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF 2024)में एक विशेष सत्र को संबोधित किया।

- 1)केवल A & B
- 2)केवल B & C
- 3)केवल A & C

4)केवल A

5)सभी A, B & C

उत्तर- 1)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर का दौरा किया।

i.PM मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के पास **वधावन बंदरगाह** की आधारशिला रखी। इस परियोजना का अनुमानित बजट लगभग **76,000 करोड़ रुपये** है।

ii.PM मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में मत्स्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को मजबूत करना है।

iii.PM मोदी ने लगभग **360 करोड़ रुपये** के कुल बजट परिव्यय के साथ **नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्प्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम** का भी शुभारंभ किया।

iv.PM मोदी ने मुंबई, महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित **5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF 2024)** में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 से 5 सितंबर 2024 को ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) नरेंद्र मोदी ने बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनेई दारुस्सलाम में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया।

B) सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड (TTC) स्टेशन के संचालन में सहयोग पर भारत और सिंगापुर के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

C) भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर; डिजिटल सहयोग; स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा अनुसंधान; और शिक्षा और कौशल विकास पर 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल A

5)सभी A, B & C

उत्तर- 2)केवल A & C

स्पष्टीकरण:

भारत के प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी 3 सितंबर से 5 सितंबर 2024 तक **ब्रुनेई दारुस्सलाम** और **सिंगापुर** की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान **हाजी हसनल बोल्किया** के निमंत्रण पर 3 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई का दौरा किया और सिंगापुर के PM **लॉरेंस वोंग** के निमंत्रण पर 4 सितंबर से 5 सितंबर 2024 तक **सिंगापुर** का दौरा किया।

- 3 सितंबर 2024 को, PM नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुस्सलाम के बंदर सेरी बेगवान में **भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर** का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत बताया।
- 4 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री (PM) **नरेंद्र मोदी** ने ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में इस्ताना नूरुल ईमान में ब्रुनेई के सुल्तान **हाजी हसनल बोल्किया** के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
- दोनों देशों के नेताओं ने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड (TTC) स्टेशन के संचालन में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान देखा।
- दोनों देशों के नेताओं ने **बंदर सेरी बेगवान**, ब्रुनेई दारुसलम और **चेन्नई**, तमिलनाडु (TN), भारत के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी की आगामी शुरुआत का स्वागत किया। इससे लोगों के बीच मजबूत संबंध बनेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार (GoI) और व्यापार और उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर ने PM मोदी की दो दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास पर 4 प्रमुख समझौतों पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- PM नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भारत का पहला **तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र** जल्द ही सिंगापुर में खुलेगा। [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

3. 9 से 10 सितंबर, 2024 को अबू धाबी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित भारत-UAE व्यापार मंच में भाग लिया।

B) UAE स्थित इंटरनेशनल रिसोर्सिज होल्डिंग RSC लिमिटेड और भारतीय कंपनियों के एक संघ: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL); खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL); और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड (OVL) ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला अन्वेषण में वैश्विक सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

C) एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ENEC) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट संचालन और रखरखाव पर एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल C
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, **शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान** 9 से 10 सितंबर 2024 को भारत के प्रधान मंत्री (PM), **नरेन्द्र मोदी** के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक 2-दिवसीय राज्य यात्रा पर थे।

- 9 सितंबर 2024 को, PM मोदी ने अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के क्राउन प्रिंस के साथ नई दिल्ली, भारत में हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक की।
- भारत और UAE ने फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे और इसका लक्ष्य 2030 तक गैर-द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।
- 10 सितंबर 2024 को, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित भारत-UAE व्यापार मंच में भाग लिया।
- भारत-UAE व्यापार मंच का विषय: "**बियॉन्ड CEPA: इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी एकाॅनोमिस**" है।
- 9 सितंबर 2024 को, भारत सरकार (GoI) और UAE सरकार ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में **5 प्रमुख समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए।**
- UAE सरकार के स्वामित्व वाली **एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ENEC)** और परमाणु ऊर्जा विभाग (DoAE) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE), **न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)**, GoI ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- UAE स्थित **इंटरनेशनल रिसोर्सिज होल्डिंग RSC लिमिटेड**, एक प्राकृतिक संसाधन निकालने वाली कंपनी; और भारतीय कंपनियों का एक संघ: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL); खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (**KABIL**); और आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन विदेश लिमिटेड (**OVL**) ने तीसरे देशों में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला अन्वेषण में वैश्विक सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। [आगे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 17 सितंबर 2024 तक झारखंड, गुजरात और ओडिशा की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) PM मोदी ने झारखंड में सात अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो मार्गों की कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी।

B) अहमदाबाद में, उन्होंने भुज रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।

C) उन्होंने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'SUBHADRA' का शुभारंभ किया। यह सबसे बड़ी, एकल महिला-केंद्रित योजना है, जिसके 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करने की उम्मीद है।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 3)केवल B & C

स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी 15-17 सितंबर 2024 को झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे।

- 15 सितंबर 2024 को झारखंड के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने झारखंड के टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर-पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
- PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।
- PM मोदी ने छह अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
- 16 सितंबर 2024 को गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो (RE-INVEST) का उद्घाटन किया।
- अहमदाबाद में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भुज रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
- 17 सितंबर 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर की अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने 2800 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया तथा 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- PM मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'SUBHADRA' का शुभारंभ किया। [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) PM मोदी ने PM विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष पूरे होने पर PM विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम में भाग लिया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

B) उन्होंने महाराष्ट्र में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क की आधारशिला रखी। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए छह PM MITRA पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी थी।

C) PM मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया।

1)केवल A & B

2)केवल A & C

3)केवल B & C

4)केवल C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 2)केवल A & C

स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को वर्धा, महाराष्ट्र का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान,

i. PM मोदी ने PM विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष को चिह्नित करते हुए राष्ट्रीय 'PM विश्वकर्मा योजना' कार्यक्रम में भाग लिया और इंडिया पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक स्मारक टिकट जारी किया।

- यह योजना 17 सितंबर, 2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पाँच वर्षों (FY 2023-24 से FY 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।

ii. उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क की आधारशिला रखी।

- भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 PM MITRA पार्क की स्थापना को मंजूरी दी थी।

iii. उन्होंने आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर महिला स्टार्ट-अप योजना शुरू की।

- इस योजना के तहत, 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- महाराष्ट्र भर में लगभग 1,50,000 युवाओं को हर साल मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा।
- इस योजना के तहत, महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए शुरुआती चरण का समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

BANKING AND FINANCE

1. किस संगठन/बैंक ने हाल ही में (अगस्त'24 में) भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना शुरू की है?

- 1)सिक््योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
- 2)रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
- 3)नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 4)स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- 5)इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी

उत्तर- 2)रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया

स्पष्टीकरण:

29 अगस्त, 2024 को, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45W के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों और अधिनियम की धारा 45U के साथ प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए "स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) इन इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) इन इंडिया" प्रवेश की।

- इस योजना का उद्देश्य IFSC में पात्र विदेशी निवेशकों को भारत सरकार (GoI) द्वारा जारी SGrBs में निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
- IFSC के भीतर संस्थाओं के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

2. किस बैंक ने हाल ही में (अगस्त'24 में) "GIGA" लॉन्च किया, जो विशेष रूप से गिग वर्कर्स और फ्रीलांसरों के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक वित्तीय सूट है?

- 1) IDFC फर्स्ट बैंक
- 2) कोटक महिंद्रा बैंक
- 3) पंजाब नेशनल बैंक
- 4) HDFC बैंक
- 5) एक्सिस बैंक

उत्तर- 4) HDFC बैंक

स्पष्टीकरण:

HDFC बैंक लिमिटेड ने भारत में गिग वर्कर्स और फ्रीलांसरों के लिए तैयार एक व्यापक वित्तीय सूट GIGA पेश किया है। यह कार्यक्रम **तेजी से फैलती गिग अर्थव्यवस्था की अनूठी वित्तीय जरूरतों** को पूरा करता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कई तरह के कर्मचारी शामिल हैं।

- GIGA एक विशेष बचत खाता, चालू खाता, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, लचीले निवेश उत्पाद, स्वास्थ्य बीमा और प्रचलन खुदरा परिसंपत्ति उत्पाद प्रदान करता है।
- GIGA बिजनेस डेबिट कार्ड **10 लाख रुपये** तक का एक्सेलरेटेड कैशबैक और व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु कवर प्रदान करता है।
- HDFC एगो गिग श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, जिसका प्रीमियम **20 रुपये प्रतिदिन** से शुरू होता है।
- **लचीला बचत खाता:** गिग वर्कर्स तिमाही बैलेंस (मेट्रो/शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये) बनाए रख सकते हैं और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP), फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

3. निम्नलिखित में से किसने हाल ही में (अगस्त'24 में) पेटिएम को पेटिएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मंजूरी दी है?

- 1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- 2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 3) वित्त मंत्रालय
- 4) भारतीय रिजर्व बैंक
- 5) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

उत्तर- 3) वित्त मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) के स्वामित्व वाली नोएडा (उत्तर प्रदेश, UP) स्थित **पेटिएम** को अपनी भुगतान सेवा शाखा पेटिएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में **डाउनस्ट्रीम निवेश** के लिए वित्त मंत्रालय (MoF) के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) से मंजूरी मिल गई है।

- इस मंजूरी के बाद, PPSL अपने पेमेंट एग्रीगेटर (PA) **लाइसेंस** के लिए फिर से आवेदन जमा करेगा। यह अपने मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज भी प्रदान करना जारी रखेगा।
- डाउनस्ट्रीम निवेश का मतलब है कि किसी भारतीय कंपनी को किसी अन्य भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या पूंजी में निवेश करके कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला है।

4. किस मंत्रालय ने हाल ही में (अगस्त'24 में) 6 नए नियम जारी किए हैं जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और अन्य लघु बचत योजना (SSS) में निवेशकों से संबंधित हैं?

- 1) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- 2) वित्त मंत्रालय
- 3) सहकारिता मंत्रालय
- 4) महिला और बाल विकास मंत्रालय

5)संचार मंत्रालय

उत्तर- 2)वित्त मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने 6 नए नियम जारी किए हैं जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और अन्य लघु बचत योजना (SSS) में निवेशकों से संबंधित हैं। ये नए नियम

1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

- इन नए नियमों को डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय लघु बचत (NSS) के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित करने के उद्देश्य से अपनाया गया है।
- इन नए विनियमों को निम्नलिखित वर्गों जैसे: अनियमित NSS, नाबालिग के नाम से खोले गए PPF खाते, विभिन्न PPF खाते रखना, अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा PPF खाते का विस्तार, अभिभावकों के बजाय दादा-दादी द्वारा शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि खाते (SSA) का नियमितीकरण में वर्गीकृत किया गया है।

5. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है?

- 1)पंजाब नेशनल बैंक
- 2)HDFC बैंक
- 3)UCO बैंक
- 4)एक्सिस बैंक
- 5)सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

उत्तर- 3)UCO बैंक

स्पष्टीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल, WB) स्थित यूनाइटेड कमर्शियल (UCO) बैंक लिमिटेड पर चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए **2.68 करोड़ रुपये** का जुर्माना लगाया है।

- RBI ने भोपाल (मध्य प्रदेश, MP) स्थित सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (CBHFL) पर नो योर कस्टमर (KYC) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए **2.1 लाख रुपये** का जुर्माना भी लगाया है।
- दोनों दंड विनियामक अनुपालन पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

6. 28 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) के 5वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) RBI के डिप्टी गवर्नर T रबी शंकर ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ साझेदारी में UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉज़िट (UPI-ICD)' लॉन्च किया।

B) जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (NBFC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की e-KYC सेतु प्रणाली को लागू करने वाली पहली NBFC बन गई है।

C) ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी ऑरियनप्रो पेमेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए RBI से प्राधिकरण प्राप्त हुआ।

- 1)केवल A & B
- 2)केवल B & C
- 3)केवल A & C
- 4)केवल A
- 5)सभी A, B & C

उत्तर- 3)केवल A & C

स्पष्टीकरण:

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 28 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, **मुंबई, महाराष्ट्र** में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा 3 दिवसीय फिनटेक सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम के 5वें संस्करण का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

- **थीम** – “ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस: रेस्पॉसिबल AI | इंकलूसिव | रेसिलिएंट”
- RBI के डिप्टी गवर्नर **T रबी शंकर** ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (**NPCI**) के साथ साझेदारी में GFF 2024 में 'UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट (**UPI-ICD**)' लॉन्च किया।
- **मास्टरकार्ड** ने ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत और वैश्विक स्तर पर '**पेमेंट पास्की सर्विस (PPS)**' शुरू की है।
- फिनटेक स्टार्टअप **POP** ने भारत का पहला मल्टी-ब्रैंड को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड, '**YES BANK POP-CLUB रुपये क्रेडिट कार्ड**' लॉन्च किया है, जिसे रुपये और YES बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
- HDB फाइनेंशियल सर्विसेज (**HDBFS**), एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (**NPCI**) की **e-KYC सेतु प्रणाली** को लागू करने वाली पहली NBFC बन गई है।
- ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी **ऑरियनप्रो पेमेंट्स** को RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ।
- VISA द्वारा संचालित **अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड** ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है - यह देश भर में 5 मिलियन से अधिक ग्राहकों को जोड़ने वाला भारत का पहला को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड बन गया है।
[अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

7. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 6 महीनों में नकद बाजार में शेयरों का एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू (ADDV) न्यूनतम _____ होना चाहिए।

- 1) 35 करोड़ रुपये
- 2) 15 करोड़ रुपये
- 3) 5 करोड़ रुपये
- 4) 25 करोड़ रुपये
- 5) 45 करोड़ रुपये

उत्तर- **1) 35 करोड़ रुपये**

स्पष्टीकरण:

30 अगस्त 2024 को, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (**SEBI**) ने वायदा और विकल्प (**F&O**) या डेरिवेटिव सेगमेंट में शेयरों के प्रवेश और निकास के मानदंडों को संशोधित किया, ताकि बाजार में स्थिरता को बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले और वित्तीय रूप से मजबूत स्टॉक ही डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग लें।

- ये नए दिशानिर्देश SEBI द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की **धारा 11(1)** और **धारा 11(2)(a)** के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए थे।
- परिपत्र तुरंत प्रभावी है, और नए मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा शेयरों को 6 महीने की गर्भावधि अवधि दी गई है।
- SEBI ने पिछले 6 महीनों में स्टॉक की मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (**MWPL**) को मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **1500 करोड़ रुपये** कर दिया है। MWPL सीमा में यह वृद्धि बाजार पूंजीकरण के कारण की गई है जो पिछली समीक्षा के बाद से **2.8 गुना** हो गई है।
- संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 6 महीनों में मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज (**MQSOS**), MQSOS को रोलिंग आधार पर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर **75 लाख रुपये** कर दिया गया है। SEBI ने उद्धृत किया है कि **2018** में की गई पिछली समीक्षा के बाद से अब औसत बाजार कारोबार 3.5 गुना से अधिक है।
- SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पिछले 6 महीनों में नकद बाजार में शेयरों का एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू (**ADDV**) न्यूनतम **35 करोड़ रुपये** (मौजूदा 10 करोड़ रुपये से) होना चाहिए। यह ADDV में उल्लेखनीय

वृद्धि के कारण है जो पिछली समीक्षा के बाद से 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

8. किस बीमा कंपनी ने GIFT सिटी में अपनी नई खोली गई ऑफशोर शाखा में अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए USD-डेनोमिनेट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च किया है?

- 1) स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 2) ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 3) लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- 4) टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 5) बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

उत्तर- 4) टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (टाटा AIA) ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT सिटी) में अपनी ऑफशोर शाखा शुरू की है, जो गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है। यह शाखा अनिवासी भारतीयों (NRI) को [टाटा AIA वेबसाइट](#) के माध्यम से USD-डेनोमिनेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ खरीदने की अनुमति देती है।

- टाटा AIA एक अनूठी अवधि के साथ परिचालन शुरू करेगा, जिसमें USD-डेनोमिनेट लाइफ प्रोटेक्ट सुप्रीम की पेशकश की जाएगी, जिससे अमेरिकी डॉलर में पॉलिसी लाभ प्राप्त होंगे।
- यह योजना 100 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती है, जिसमें मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता और गंभीर बीमारी जैसे जोखिम शामिल हैं।

9. किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में (सितंबर '24 में) पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई टर्म इंश्योरेंस योजना "इनकम सुरक्षा प्लान" शुरू की है?

- 1) लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- 2) एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 3) HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 4) आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
- 5) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

उत्तर- 4) आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड (ABSLI) और गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 'इनकम सुरक्षा प्लान' शुरू की है, जो एक नई टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसीधारक के परिवार को आजीवन आय प्रदान करती है।

i. यह आय सुरक्षा प्लान पॉलिसीधारक के नामांकित व्यक्तियों को आजीवन आय भी प्रदान करती है।

ii. यह आय न केवल कर-मुक्त है, बल्कि इसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के लिए पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक रूप से संयोजित भी किया जाता है, जिसकी शुरुआत योजना खरीदे जाने के दिन से होती है। एकल लेनदेन के लिए पहले वर्ष के प्रीमियम पर 9% तक की छूट दी जाती है।

10. किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में (अगस्त '24 में) RuPay और यस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत का पहला मल्टी-ब्रैंड को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?

- 1) कोवरज़ी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
- 2) BranchX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- 3) टेकफिनी
- 4) POPtech ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड

5) एमस्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
उत्तर- 4) POPtech ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड

स्पर्धीकरण:

POPtech ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड (POP), एक फिनटेक स्टार्टअप ने भारत का पहला मल्टी-ब्रैंड को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड, 'YEB BANK POP-CLUB RuPay क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया है, जिसे RuPay और यस बैंक लिमिटेड की साझेदारी में विकसित किया गया था।

- इसे 2024 ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF), मुंबई (महाराष्ट्र) में यस बैंक के क्रेडिट कार्ड बिक्री और साझेदारी के प्रमुख अमित सिन्हा और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में कॉर्पोरेट और फिनटेक रिलेशनशिप के प्रमुख नलिन बंसल की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
- कार्ड में कोई जॉइनिंग शुल्क नहीं है और यह जॉइनिंग लाभों के एक विशेष सेट के साथ आता है। कार्डधारक POPcoins का उपयोग करके प्रत्येक लेनदेन पर पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता सभी ऑनलाइन लेनदेन के लिए 10% POPcoins, ऑफलाइन लेनदेन के लिए 2% POPcoins और POP UPI के साथ कार्ड का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त 5% POPcoins कमा सकते हैं।

11. किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में (अगस्त'24 में) अपना मार्केट-लिंकड पेंशन उत्पाद 'सिग्रेचर पेंशन' लॉन्च किया है जो ग्राहकों को लागत और टैक्स-एफिसिएंट रिटायरमेंट प्लान बनाने में सक्षम बनाता है?

- 1) लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- 2) बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 3) ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 4) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 5) टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

उत्तर- 3) ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

स्पर्धीकरण:

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 'ICICI प्रू सिग्रेचर पेंशन' लॉन्च की है, जो एक मार्केट-लिंकड पेंशन उत्पाद है जो ग्राहकों को लागत और टैक्स-एफिसिएंट रिटायरमेंट प्लान बनाने में सक्षम बनाता है।

- नया उत्पाद उपभोक्ताओं को 100% इक्विटी एक्सपोजर और इक्विटी, डेट और बैलेंस्ड फंड के बीच स्थानांतरित करने की क्षमता के साथ अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को अनुकूलित करने की पेशकश करता है।
- इसमें दो फंड, ICICI प्रू पेंशन इंडिया ग्रोथ फंड और ICICI प्रू पेंशन बैलेंस्ड फंड शामिल हैं।

12. किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में (अगस्त'24 में) विकलांग व्यक्तियों (PWD) की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई 'स्पेशल केयर गोल्ड' नाम से भारत की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है?

- 1) कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 2) ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 3) SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 4) स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 5) फेडरल बैंक लिमिटेड

उत्तर- 4) स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

स्पर्धीकरण:

चेन्नई, तमिलनाडु (TN) स्थित स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टार हेल्थ इंश्योरेंस) ने भारत की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी 'स्पेशल केयर गोल्ड' लॉन्च की, जिसे विकलांग व्यक्तियों (PWD) की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह पॉलिसी 'द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016' के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए और 'ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिविटी वायरस (HIV) एंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (AIDS) (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट, 2017' के तहत परिभाषित HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है।

- इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इंश्योरेंस क्षेत्र में आय सृजन के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- **18 से 65 वर्ष** की आयु का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ उठा सकता है। आश्रित बच्चों को नवजात शिशु से लेकर **17 वर्ष** की आयु तक कवर किया जाता है।
- यह पॉलिसी **4,00,000 रुपये** और **5,00,000 रुपये** के व्यक्तिगत कवरेज विकल्पों के साथ **1 वर्ष की अवधि** प्रदान करती है।

13. किस बैंक ने हाल ही में (अगस्त'24 में) ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2024 में दो अभिनव डिजिटल समाधान - 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-ऑटोमेटेड टेलर मशीन (UPI-ATM)' और 'भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस' लॉन्च किए हैं?

- 1) बंधन बैंक
- 2) एक्सिस बैंक
- 3) HDFC बैंक
- 4) केनरा बैंक
- 5) फेडरल बैंक

उत्तर- 2) एक्सिस बैंक

स्पष्टीकरण:

एक्सिस बैंक लिमिटेड ने मुंबई, महाराष्ट्र में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2024 में दो अभिनव डिजिटल समाधान - 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-ऑटोमेटेड टेलर मशीन (UPI-ATM)' और 'भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस' लॉन्च किए। दोनों पहल इसके खुदरा और थोक बैंकिंग व्यवसाय के लिए हैं।

- **UPI-ATM** किसी भी UPI एप्लीकेशन (ऐप) का उपयोग करके कार्डलेस कैश विथड्रावल और डिपॉजिट सिस्टम है।
- यह **भारत का पहला एंड्रॉइड कैश रीसाइक्लर** है जो UPI के साथ एकीकृत है, जो ग्राहकों को किसी भी UPI-इनेबल्ड एप्लीकेशन का उपयोग करके इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश डिपॉजिट (ICD) और इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी (ICCW) दोनों लेनदेन करने की अनुमति देता है।
- **भारत कनेक्ट** (पूर्व में भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS) **फॉर बिजनेस** को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।

14. उस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजना का नाम बताएं जिसे हाल ही में (अगस्त'24 में) बैंक ऑफ इंडिया (BoI) द्वारा 7.25% तक की ब्याज दर के साथ लॉन्च किया गया था।

- 1) स्टार धन वृद्धि
- 2) अमृत वृष्टि
- 3) MAHA-DOC
- 4) जीवन समर्थ
- 5) सुकन्या समृद्धि योजना

उत्तर- 1) स्टार धन वृद्धि

स्पष्टीकरण:

भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में से एक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने 'स्टार धन वृद्धि' नामक एक सावधि जमा (FD) योजना शुरू की है, जिसकी अवधि सीमा **333 दिन** है और यह 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी।

- स्टार धन वृद्धि के तहत, ग्राहक 3 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं।
- 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर आम नागरिकों के लिए बैंक की FD ब्याज दरें अब 3% से 7.25% तक हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों (60-79 वर्ष) के लिए ब्याज दरें 3% से 7.75% तक हैं, और अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए ब्याज दरें 3% से 7.90% तक हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों को 6 महीने से 3 साल की अवधि के लिए अपने खुदरा सावधि जमा (RTD) (3 करोड़ रुपये से कम) पर अतिरिक्त 50 आधार अंक (bps) प्राप्त होंगे।

15. किस संगठन ने हाल ही में (सितंबर'24 में) भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) स्टार्ट-अप के लिए नवाचार, अनुसंधान और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान-कोझिकोड (IIMK) की नवाचार, उद्यमशीलता और उद्यमिता प्रयोगशाला (IIMK LIVE) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 1) रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
- 2) NITI आयोग
- 3) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- 4) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
- 5) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग

उत्तर- 1) रिजर्व बैंक इनोवेशन हब

स्पष्टीकरण:

केरल स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान-कोझिकोड (IIMK) की नवाचार, उद्यमशीलता और उद्यमिता प्रयोगशाला (IIMK LIVE) और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) स्टार्ट-अप के लिए नवाचार, अनुसंधान और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- MoU का उद्देश्य एक एकीकृत और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो साझा संसाधन विशेषज्ञता और नवीन रणनीतियों के माध्यम से फिनटेक विकास और विकास को गति प्रदान करता है।
- यह सहयोग भारत के फिनटेक परिदृश्य में विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

16. ग्लोबल पेमेंट हब पेसिक्वोर डेटा के अनुसार, भारत के UPI ने अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच लगभग रुपये के लेनदेन संसाधित किए हैं, जो दुनिया के शीर्ष डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म से आगे

निकल गया है।

- 1) 34.367 लाख करोड़
- 2) 46 लाख करोड़
- 3) 78 लाख करोड़
- 4) 81 लाख करोड़
- 5) 99.68 लाख करोड़

उत्तर- 4) 81 लाख करोड़

स्पष्टीकरण:

ग्लोबल पेमेंट हब पेसिक्वोर के आंकड़ों के अनुसार, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच लगभग **81 लाख करोड़ रुपये** के लेन-देन संसाधित किए हैं, जो दुनिया के शीर्ष डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म से आगे निकल गया है। यह साल-दर-साल (YoY) **37% की वृद्धि** दर्शाता है।

- भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में सबसे आगे है, जहाँ 40% से अधिक पेमेंट डिजिटल रूप से किए जाते हैं और उनमें से अधिकांश के लिए UPI का उपयोग किया जाता है।
- UPI ने प्रति सेकंड 3,729.1 लेन-देन संसाधित किए, जो 2022 में 2,348 से 58% अधिक है।
- **जुलाई 2024** में UPI लेन-देन 20.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो एक महीने में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK) स्थित **स्क्रिल** 1,553.8 लेनदेन प्रति सेकंड के साथ दूसरी सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक पेमेंट पद्धति बन गई और 2023 में 49 बिलियन लेनदेन संसाधित किए। ब्राजील स्थित **पिक्स** 1,331.8 लेनदेन प्रति सेकंड के साथ तीसरी सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक भुगतान पद्धति है।

17. किस फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट गेटवे को हाल ही में (अगस्त'24 में) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है?

- 1) PayU
- 2) EBANX
- 3) पेशार्प

4)टेरापे

5)रेजरपे

उत्तर- 3)पेशार्प

स्पष्टीकरण:

30 अगस्त 2024 को, चेन्नई (तमिलनाडु, TN) स्थित फिनटेक स्टार्टअप **पेशार्प प्राइवेट लिमिटेड** को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ।

- पेशार्प को दिसंबर 2022 में **इन-प्रिसिपल PA लाइसेंस** प्राप्त हुआ है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 27001:2022 और प्रणाली और संगठन नियंत्रण (SOC) 2 मान्यताएँ हैं।

18. अगस्त 2024 में, कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने खुद को _____ के रूप में रीब्रैंड किया है।

1)स्कॉट कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

2)बर्न कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

3)ज्यूरिख कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

4)HSBC कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

5)नेटवेस्ट कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

उत्तर- 3) **ज्यूरिख कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड**

स्पष्टीकरण:

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित **कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** ने ज्यूरिख इश्योरेंस ग्रुप द्वारा जून 2024 में कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 70% अधिग्रहण के बाद, **ज्यूरिख कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** के रूप में अपना नाम रीब्रैंड किया। यह ब्रैंड विश्वास, नवाचार, अखंडता और ग्राहक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

- ज्यूरिख कोटक जनरल इश्योरेंस कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, **ज्यूरिख इश्योरेंस ग्रुप** और **कोटक महिंद्रा बैंक**, जो भारत में सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली नॉन-लाइफ इश्योरेंस प्रेंचाइजी में से एक है, के बीच 70:30 संयुक्त उद्यम (JV) है।
- अपनी रीब्रैंडिंग के अनुरूप, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल का भी पुनर्गठन किया है, जिसमें सुरेश अग्रवाल को प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO); और श्रीनिवास इंजेती को अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक (ID) के रूप में शामिल किया गया है।

19. हाल ही में (सितंबर'24 में) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा लिस्टिंग ओब्लिगेशंस एंड डिसक्लोशर्स के नियमों को कारगर बनाने के लिए गठित 22 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

1)राजीव खेर

2)अभय प्रसाद होता

3)राम सुब्रमण्यम गांधी

4)सुनील मेहता

5)संजय नायर

उत्तर- 3)राम सुब्रमण्यम गांधी

स्पष्टीकरण:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने **लिस्टिंग ओब्लिगेशंस एंड डिसक्लोशर्स** के नियमों को कारगर बनाने के लिए **22 सदस्यीय एडवाइजरी कमिटी** गठित की है।

- **एडवाइजरी कमिटी ऑन लिस्टिंग ओब्लिगेशंस एंड डिसक्लोशर्स (ACLOD)** की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व डिप्टी गवर्नर **राम सुब्रमण्यम गांधी** करेंगे।
- कमिटी डिसक्लोशर्स आवश्यकताओं, लिस्टिंग और पोस्ट-लिस्टिंग ओब्लिगेशंस, हॉर्मोनाइज़ेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर SEBI को सलाह प्रदान करेगी।